● वर्ष-4
● अंक-54
रायपुर, गुरुवार
10 अक्टूबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6»»» कम लागत से शुरु कर सकते है...

महंगाई पर सख्त लगाम जरूरी नहीं तो यह फिर बढ़ सकती है

मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद मूल्य वृद्धि पर बोले दास

नई दिल्ली। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, दूसरी ओर आम आदमी महंगाई से परेशान है। खाने-पीने के चीजों की कीमतों में पिछले कुछ महीनों के दौरान बड़ा इजाफा देखा गया है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी महंगाई पर टिप्पणी की। दो महीने के अंतराल पर होने वाली मौद्रिक समीक्षा के बाद गवर्नर दास ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक को महंगाई पर कड़ी नजर रखते हुए इस पर सख्त लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो यह फिर से बढ़ सकती है।

महंगाई दर के अनुमान 4.5% पर बरकरार - भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा महंगाई के अपने अनुमान को बुधवार को 4.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। एमपीसी की बैठक के बाद दास ने कहा कि लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य (एफआईटी) ढांचे को 2016 में लागू किए जाने के बाद से आठ वर्ष पूरे हो गए हैं और यह भारत में 21वीं सदी में किया गया एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार है।

दास के अनुसार केंद्रीय बैंक ने एफआईटी के तहत यह सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा महंगाई दर दो प्रतिशत उतार-चढ़ाव के साथ चार प्रतिशत पर बनी रहे। आरबीआई ने 2024-25 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के अपने अनुमान को 4.5 प्रतिशत पर बनाए रखा है। महंगाई दर के दूसरी तिमाही में 4.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए मुद्रास्फीति के 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

दास ने कहा, " प्रतिकूल आधार प्रभाव तथा खाद्य पदार्थों कीमतों में तेजी से सितंबर में महंगाई दर में तेजी देखने को मिल सकती है। अन्य कारकों के अलावा 2023-24 में प्याज, आलू और चना दाल के उत्पादन में कमी इसकी प्रमुख वजह होगी।"

अच्छे मानसून के कारण महंगाई से राहत की उम्मीद- हालांकि दास ने कहा कि अच्छे मानसून, बढ़िया खरीफ फसल, अनाज के पर्याप्त भंडार और आगामी रबी मौसम में बेहतर फसल की उम्मीद से इस वर्ष की चौथी तिमाही में महंगाई दर में नरमी आ सकती है। दास ने कहा कि प्रतिकूल मौसम और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने की स्थिति में मुद्रास्फीति के ऊपर जाने का भी जोखिम है। अक्तूबर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में काफी उतार-चढ़ाव रहा है। जुलाई और अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मियों के हाथ लगी मायूसी

नहीं मिली महंगाई भत्ते की सौगात

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बुधवार को सरकार, महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग की। उसमें महंगाई भत्ते का कहीं कोई जिक्र नहीं था। दशहरा भी इसी सप्ताह है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष डीए/डीआर की दरों में बढ़ोतरी करने से जुड़ी फाइल नहीं पहुंची है। अब दीवाली से पहले महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की दरों में चार फीसदी की वृद्धि करने की घोषणा हो सकती है। वर्तमान में 50 प्रतिशत दर के हिसाब से डीए/डीआर मिल रहा है।

बता दें कि डीए/डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा, सितंबर माह में कर दी जाती है। इस बार अक्तूबर प्रारंभ हो गया है, लेकिन इन भत्तों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। तीन अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि रेल कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को यह आस बंध गई थी कि 9 अक्तूबर की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की घोषणा कर दी जाएगी।

कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। पत्र में कहा गया कि इन भत्तों का भुगतान, अक्तूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। अगर अक्तूबर माह में केंद्र सरकार, भत्तों व बोनस देने की घोषणा करती है तो उनका भुगतान नवंबर में हो सकेगा। दूसरी तरफ इन भत्तों को तय समय पर जारी न कर सरकार, खुद लाभ कमा रही है। एसबी यादव के अनुसार, वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर एक जुलाई से देय है। अभी तक इन भत्तों की घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जाती थी। इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर्मचारियों को तीन महीने का बकाया भुगतान किया जाता था। इन भत्तों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में गहरा असंतोष है। नवरात्र, दुर्गा पूजा उत्सव, दशहरा व दीवाली जैसे बड़े त्योहार हैं, लेकिन अभी तक डीए की घोषणा नहीं हो सकी है। यादव ने अपने पत्र में कहा, परिसंघ उपरोक्त मामले में आपके तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है। वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे तत्काल प्रभाव से डीए/डीआर देने की घोषणा करें।

केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते डीए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कई माह देरी से की जाती है। इसके द्वारा सरकार, खुद लाभ कमा लेती है। चूंकि डीए/डीआर की दरों में हुई बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का भार पड़ता है। ऐसे में सरकार, डीए/डीआर की घोषणा, तीन चार माह देरी से करती है। इस अवधि के दौरान सरकार का पैसा निवेश होता है, जिस पर उसे अछा खासा ब्याज मिलता है। नियमानुसार, पहली जनवरी और पहली जुलाई से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार हर दफा यह घोषणा करने में तीन चार माह की देरी कर देती है। अमूमन सितंबर में डीए की घोषणा हो जाती है, लेकिन इस बार अभी तक सरकार ने डीए बढ़ोतरी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है।

अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड के वरिष्ठ सदस्य सी.श्रीकुमार ने कहा, सरकार को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। जब पहली जनवरी और पहली जुलाई से डीए बढ़ोतरी का नियम है तो इसमें कई माह की देरी क्यों हो रही है। केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मियों और 62 लाख पेंशनरों को डीए/डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलता है। ऐसे में सरकार को हजारों करोड़ रुपये कर्मियों की सेलरी में देने पड़ते हैं।

कांग्रेस का ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप, निर्वाचन आयोग से जांच का आग्रह

नई दिल्ली। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम में साफ तौर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग से जांच करने का आग्रह किया। कांग्रेस ने कहा कि निर्वाचन आयोग से पूरी जांच करने और विसंगतियों वाली ईवीएम को सील करके जांच पूरी होने तक सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मतगणना को लेकर संदेह है क्योंकि हरियाणा चुनाव के परिणाम आश्चर्य में डालने वाले हैं, सभी को लग रहा था कि कांग्रेस अगली सरकार बनाएगी। हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले हैं क्योंकि सभी को लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। सभी सर्वे रिपोर्ट में यही था लेकिन हुआ ये कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस हर जगह आगे चल रही थी, लेकिन जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस पिछड़ रही थी। हमें कई शिकायतें मिली हैं। कई जगहों पर वोटों की गिनती में देरी हुई। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वे सभी शिकायतों पर गौर करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आज केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, अजय माकन, जयराम रमेश, भूपिंदर सिंह हुड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। हमने आज चुनाव आयोग को अवगत कराया।

करीब 20 शिकायते जो हमारे पास आई थी उसमें से 7 लिखित शिकायतों में ऐसी मशीनें थीं जो वोटिंग के दिन 99त्न दिखा रही थी और अन्य सामान्य मशीनें 60-70% दिखा रही थी। इससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया। हमने मांग की कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील कर सुरक्षित रखा जाए। हमने चुनाव आयोग को यह भी कहा कि अगले 48 घंटों में हम बाकी शिकायतें भी उनके सामने रखेंगे। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वह जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित एक पत्र में कहा कि वह अप्रत्याशित परिणामों पर पार्टी अध्यक्ष के रुख को मानता है, न कि पार्टी के कुछ नेताओं के इस रुख को कि परिणाम स्वीकार्य नहीं हैं। कांग्रेस नेताओं को बयान पर आयोग ने कहा कि देश की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत में सामान्य अर्थों में उपर्युक्त जैसा अभूतपूर्व बयान अनसुना है, यह मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के वैध हिस्से से बहुत दूर है.

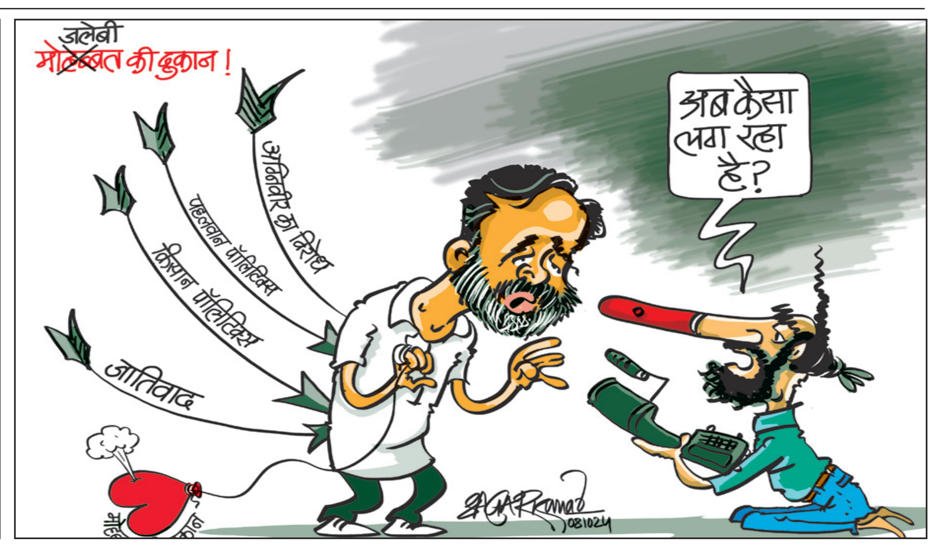

प्रमुख समाचार

आज वियनतियाने के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 10-11 अक्तूबर को लाओ पीडीआर की यात्रा पर होंगे। इनकी मेजबानी लाओ पीडीआर कर रहा है। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले बुधवार को विदेश मंत्रालय ने उनके दौरे को लेकर अहम जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत आसियान से संबंधित सभी तंत्रों को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिपांडोन और अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) जयदीप मजूमदार ने कहा कि यह दसवां मौका होगा जब प्रधानमंत्री आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री अन्य नेताओं के साथ भारत-आसियान संबंधों में प्रगति का आकलन करने के साथ ही संबंधों के भविष्य की दिशा निर्धारित करेंगे। उन्होंने कहा कि लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (पीडीआर) के पीएम सिपांडोन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी वियनतियाने के दौरे पर जा रहे हैं। मजूमदार ने कहा कि पीएम मोदी और सिपांडोन के बीच दिपक्षीय बैठक होगी।

लालू यादव के करीबी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, संपत्ति जब्त

आरा/पटना। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में शुमार और भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा के पूर्व विधायक अरुण यादव पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अरुण यादव की 19.32 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इसमें आरा के अगिआंव स्थित उनकी हवेली और पटना में कई फ्लैट्स शामिल हैं। इसके अलावा, उनके बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया है। ईडी ने इस कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्ग (पूर्व में ट्विटर) पर दी। ईडी द्वारा किए गए इस कदम से बिहार की राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है, क्योंकि अरुण यादव को लालू यादव का बेहद करीबी माना जाता है। फिलहाल, अरुण यादव की पत्नी किरण देवी संदेश विधानसभा से आरजेडी की विधायक हैं। ईडी ने अपने बयान में बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरुण यादव की आरा के अगिआंव स्थित आलीशान हवेली, पटना में कई अचल संपत्तियों और बैंक खातों को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई लंबे समय से चल रहे एक जांच के सिलसिले में की गई है।

टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा की हालत नाजुक

मुंबई। भारत के सबसे बड़े समूह टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा की तबीयत एक बार फिर गंभीर हो गई है। जानकारी के मुताबिक उन्हें मुम्बई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इससे दो दिन (7 अक्तूबर) पहले भी उनके स्वास्थ्य बिगड़ने की सूचना समाचार चैनल में प्रसारित हुई थी। हालांकि इस मामले में उनके ऑफिशियल एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट के जरिए अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी कि, वो स्वस्थ हैं। उन्होंने खुद इन दावों का खंडन किया और अपने आईसीयू में भर्ती होने के दावों को अफवाह करार दिया था। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में हाल ही में फैल रहीं अफवाहों से अवगत हूं। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये दावे निराधार हैं। मैं फिलहाल अपनी उम्र और सेहत संबंधी जरूरी चिकित्सा जांच करवा रहा हूं। चिंता का कोई बात नहीं है। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि जनता और मीडिया गलत सूचना फैलाने से बचें। रतन नवल टाटा, एक भारतीय व्यापारी, निवेशक, दानवीरऔर टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष हैं।

जम्मू कश्मीर के रिजल्ट पर पाक मना रहा था खुशियां

जम्मू। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 में से 42 सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसे में कश्मीर में बीजेपी की हालत देख पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन एक इजरायली व्यक्ति ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। इस इजरायली ने भारत को एक संदेश दिया है। एक पाकिस्तान न्यूज चैनल ने लिखा है कि पीएम मोदी कश्मीर में हार गए हैं। पाकिस्तान के हर अखबरा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बारे में बड़े बड़े हेडलाइन लिए हैं। कई यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि मोदी ने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया लेकिन कश्मीर की जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। पाक मूल के अमेरिकी साजिद तरार ने कहा कि घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जम्मू में भाजपा बढ़त पर रही है। ऐसे में हो सकता है कि केंद्र की भाजपा सरकार अब कश्मीर के लिए फंड जारी ना करे। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट को हेडलाइन दी है, भाजपा को हराया, उमर अब्दुल्ला करेंगे कश्मीर का नेतृत्व। जियो टीवी ने कहा है कि 370 रद्द किए जाने के बाद कश्मीर को पहली सरकार मिलने जा रही है।

हिजबुल्ला पर कार्रवाई करो, वरना गाजा जैसा हाल-नेतन्याहू

तेल अवीव। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में चेतावनी दी कि अगर लेबनान की सीम के भीतर हिजबुल्ला को काम करने की अनुमति दी जाती है, तो उसका हाल भी गाजा जैसा हो सकता है। नेतन्याहू का यह बयान उस समय आया है, जब इस्राइली सेना ने लेबनान के दक्षिणी छोर पर हिजबुल्ला के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज की है और लोगों को इलाके को खाली करने की सलाह दी है। नेतन्याहू ने लेबनान की जनता से अपील की है कि वे अपने देश को हिजबुल्ला के चंगुल से मुक्त करें, ताकि आगे की तबाही से बचा जा सके। उन्होंने कहा, आपके पास अपने देश को बचाने का अवसर है। वरना, एक लंबा युद्ध आपके देश को गर्त में ले जाएगा और आपको भी गाजा की तरह तबाही का सामना करना पड़ सकता है। इस्राइली प्रधानमंत्री ने कहा कि इस्राइल ने हिजबुल्ला की क्षमताओं को कमजोर कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस्राइली सेना ने बेरूत में हिजबुल्ला के खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाया है। इस्राइल की इस कार्रवाई का मकसद हिजबुल्ला के सैन्य ढांचे को नष्ट करना है। इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव उस समय और बढ़ गया.

अनुच्छेद 370 से फ्री बिजली-गैस तक के वादे पर फैसले कैसे लेगी जम्मू कश्मीर की नई सरकार?

शिवेंद्र तिवारी

अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए यह पहला विधानसभा चुनाव था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर 10 साल बाद फिर सरकार बनाने का जनादेश हासिल कर लिया। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय है। हालांकि, वह अब केंद्र शासित प्रदेश के मुखिया होंगे न कि पूर्ण राज्य के। जम्मू कश्मीर की सत्ता में काबिज होने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव के दौरान तमाम ऐसे वादे किए जिन पर देशभर में चर्चा हुई। नेकां ने अपनी सरकार आने पर अनुच्छेद 370 की बहाली से मुफ्त बिजली और गैस सिलेंडर देने का का वादा किया। एनसी ने %राजनैतिक कैदियों% की रिहाई का भी वादा किया है। विरोधियों का आरोप है कि इसकी आड़ में पत्थरबाजों को छोड़ने का आश्वासन दिया गया। हालांकि, नई सरकार के लिए हलचल बढ़ने के साथ ही अनुच्छेद 370 समेत तमाम मुद्दों पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार खुद फैसले ले सकती है।

अनुच्छेद-370 में बदलाव

जवाब- संविधान में अनुच्छेद-370 को अस्थायी और तात्कालिक प्रावधान के तौर पर शामिल किया गया था, जिसे अगस्त 2019 में निष्प्रभावी बना दिया गया। इसका विरोध करने वालों के दो बड़े तर्क थे। पहला-संविधान सभा की समाप्ति के बाद इसे खत्म नहीं किया जा सकता है और इसे खत्म करने से जम्मू-कश्मीर के भारत विलय में सवाल खड़े हो जायेंगे, लेकिन 2019 के बदलावों से साफ है कि संसद सर्वोच्च है और इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मान्यता भी मिल गयी है।

केन्द्र शासित प्रदेश की नई सरकार के पास अनुच्छेद-370 को पुन- बहाल करने के लिए कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होंगे। इस

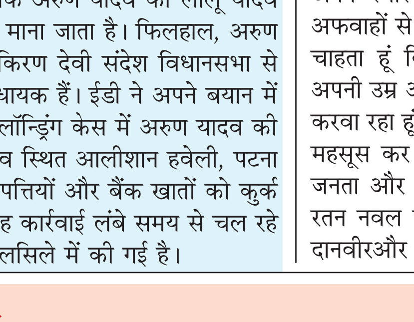

बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और विधानसभा किसी प्रस्ताव को पारित भी करें तो केन्द्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल के अनुमोदन के बगैर उसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। अनुच्छेद-370 की स्थिति को बहाल करने के लिए राज्य विधानसभा के प्रस्ताव और एलजी के अनुमोदन के बाद संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से क़ानून में बदलाव को राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है।

अनुच्छेद -35-ए में बदलाव

जवाब- साल-1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के आदेश से अनुच्छेद -35-ए का प्रावधान जोड़ा गया था। उसके अनुसार जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद 1956 में जम्मू-कश्मीर के संविधान में ऐसे प्रावधान किये गये जिसके अनुसार वहां के स्थायी नागरिक को ही सम्पत्ति, रोजगार और सरकारी योजनाओं के लाभ लेने का हक दिया गया। उसके अनुसार ही भारत के किसी अन्य राज्य के नागरिक जम्मू-कश्मीर में अचल सम्पत्ति नहीं खरीद सकते थे। उस कानून के अनुसार राज्य से बाहर शादी करने वाली महिलाओं के बच्चों को स्थायी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता था। वह कानून अनुच्छेद-14 की समानता के खिलाफ होने के साथ महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण था। अनुच्छेद-19 के तहत लोगों को पूरे देश में रहने और रोजगार का अधिकार है। इस भेदभावपूर्ण और अलगाववाद को बढ़ाने वाले संवैधानिक प्रावधान को पांच साल पहले संसद में कानूनी बदलाव से हटा दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मान्यता मिल गई है। इसलिए यूटी की नई सरकार और विधानसभा के पास अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद -35-ए को बहाल करने के बारे में कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होंगे।

राजनीतिक कैदियों की रिहाई

जवाब- कानून की किताबों में राजनीतिक कैदियों जैसा कोई शब्द नहीं है। जेलों में बंद कैदी दो तरह के होते हैं। पहला जिन्हें अदालत से सजा मिल गई है या फिर उनकी सजा फाइनल हो चुकी है। ऐसे सजा याफ्ता कैदियों को अच्छे आचरण के आधार जल्द रिहाई देने के लिए कानून में प्रावधान हैं। इसके लिए जेल प्रशासन और राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार यूटी के उपराज्यपाल ही आखिरी फैसला ले सकते हैं। दूसरी श्रेणी में विचाराधीन कैदी होते हैं, जिन्हें अदालत से जमानत मिल सकती है। ऐसे मामलों में राज्य सरकार मुकदमे वापस लेने का भी निर्णय ले सकती है। लेकिन ऐसे सभी मामलों में राज्य मंत्रिमण्डल की सिफारिश से उप-राज्यपाल के पास ही निर्णय लेने का अंतिम अधिकार होगा।

फ्री बिजली और सिलेंडर देने के वायदे

जवाब- ऐसे मामलों में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला-क्या इन योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से मदद मिल रही है और क्या राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी योजनाओं को एलजी के औपचारिक अनुमति की जरुरत हो सकती है। जम्मू-कश्मीर के यूटी को दिल्ली से ज्यादा संवैधानिक अधिकार और स्वायत्ता हासिल होगी। लेकिन राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते ऐसे मामलों में एलजी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी का खुलासा

एक दंपती समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने मुंबई से किया गिरफ्तार

दुर्ग। दुर्ग में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एक दंपति समेत तीन आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। तीनो आरोपी विदेश में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के नाम पर सायबर स्कैम का काम करवाया करते थे। साथ ही उनके पासपोर्ट जप्त कर लिए जाते थे। इस मामले में पुलिस दो अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।

प्रदेश में जिसके तहत आरोपी नौकरी लगने के नाम पर लोगों को गल्फ कंट्री भेजा करते थे भिलाई का भी एक व्यक्ति भारत आने के बाद उसने अपनी शिकायत साइबर पुलिस से की इसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की। जिसमे मुंबई के गोरेगांव में गोल्डन लिंक सर्विस के नाम से दो एजेंट भारत से लोगों को गल्फ कंट्री भेजा करते थे पकड़े जाने के बाद गिरोह के अन्य लोगो की पतासाजी में जुट गई है।

विदेश में दूसरे प्रदेशों के 10 से अधिक लोगो वहां फंसे है जो भारत आना चाहते है उनके लिए। दुर्ग पुलिस ने भारत सरकार से भी पत्राचार करेगी।मुंबई में गोल्डन ट्रायंगल सर्विस एजेंसी खोलकर सीधे-साधे लोगों को गल्फ कंट्री में नौकरी दिलाने के नाम पर पहले उनसे लाख रूपये लेकर विदेश भेज जाता है उसके बाद एजेंट का कमीशन भी लिया जाता था इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह उनसे साइबर स्कैम का काम कराया जाता था। भिलाई के भी एक युवक इनके झांसे में आ गया। उसे कंबोडिया के लाओस भेजा गया। लेकिन वहा उसके पासपोर्ट को जप्त कर उसे मानसिक प्रताड़ना दिए जाने लगा।

इस बीच उससे किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं किया गया था। जिससे परेशान होकर शिकायतकर्ता युवक द्वारा भी प्लेसमेंट एजेंसी पर लगातार दबाव बनाने लगा। जिसके कारण एजेंसी ने उसे भारत भेज दिया। भारत वापस आने के बाद अपनी आप बीती और शिकायत को उसने दुर्ग पुलिस के उच्च अधिकारियों को बताया। जिसके बाद पुलिस की सायबर एक्सपर्ट टीम ने इस मामले में अपराध दर्ज कर तफ्तीश आगे बढ़ाया। और मुंबई के गोरेगांव स्थित गोल्डन लिंक सर्विस के नाम से संचालित एजेंसी के माध्यम से साजन,उनकी पत्नी और रफी खान मिलकर लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के नाम पर रू. 200000 की वसूली किया करते थे लेकिन विदेश में जाने के बाद यह लोग उनके ग्रुप से जुड़े लोग उनसे साइबर स्कैम करवाया करते थे भिलाई का शिकायतकर्ता भी उनके जब चुंगल से छूटकर भारत आया जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तार में जुट गई थी।

आईपीएस चिराग जैन ने बताया कि शिकायतकर्ता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी में जुट गई थी पुलिस ने तीनो आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है तीनो आरोपी विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर एजेंट के रूप में काम करते थे और कमीशन लेते थे। आरोपियों ने शिकायतकर्ता को ओमान लाओसा में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम बताकर उसके वहां साइबर स्कैम का काम कराया जा रहा था। पुलिस विदेश में फंसे अन्य लोगो को भारत लाने का प्रयास कर रही है वही 2 अन्य फरार लोगो की पतासाजी में जुट गई है।

मारे गए नक्सलियों के शव परिजनों को सौंपे गए

अबूमझमाड़ एनकाउंटर : दो डेड बॉडी लेने कोई नहीं आया

जगदलपुर। अबूझमाड़ के थुलथुली, गवाड़ी, नेंदुर के जंगलों में 4 अक्टूबर को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए। मारे गए सभी नक्सलियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। सभी शवों का पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया। इन 31 शवों में 14 शव दंतेवाड़ा, 10 शव बीजापुर और 7 शव को मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रवाना किया गया। इनमें 2 शव अभी डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में ही रखे गए हैं। इन शवों को लेने उनके परिजन नहीं आए हैं।

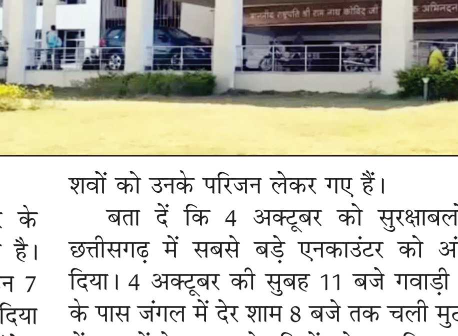

जानकारी के मुताबिक जगदलपुर शहर के मेडिकल कॉलेज में 7 शवों को लाया गया है। जिनमें 4 महिला और 3 पुरुष के शव हैं। इन 7 शवों में 5 शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। 2 शव अभी भी मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के शव गृह में रखे हुए हैं। भेजे गए माओवादियों के शव में फूलों उर्फ सुंदरी, बसंती, सोमे, बुधराम, जनीला और अर्जुन नाम के माओवादियों के शव हैं। सोहन और सोमे का शव अभी भी मेडिकल कॉलेज में रखा हुआ है। अब तक इनके परिजन शव लेने नहीं पहुंचे हैं। बाकी शवों को उनके परिजन लेकर गए हैं।

बता दें कि 4 अक्टूबर को सुरक्षाबलों ने छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया। 4 अक्टूबर की सुबह 11 बजे गवाड़ी गांव के पास जंगल में देर शाम 8 बजे तक चली मुठभेड़ में जवानों ने 31 माओवादियों को मार गिराया था, जिनमें अबूझमाड़ की बड़ी लीडर नीति उर्फ उर्मिला मारी गई। घटना स्थल से नीति के अलावा अन्य 30 माओवादियों का शव बरामद किया गया था। साथ ही घटना स्थल से एलएमजी, एके-47, इंसास, एसएलआर, बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल सेल सहित अन्य विस्फोटक भी मिले।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में नगर पालिका एवं पंचायत निर्वाचन

त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली तैयार करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। आगामी नगरपालिका और पंचायत आम-उप निर्वाचन हेतु त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली तैयार करने कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर ने निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में तिथिवार किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। प्रथम चरण में 14 अक्टूबर तक जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना है। इस संबंध में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समन्वय से निर्धारित तारीख तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, परियोजना निदेशक डीआरडीए के पी तेंदुलकर, संयुक्त कलेक्टर प्रिया गोयल, एसडीएम पेण्ड्रारोड अमित बेक सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि नगरपालिका आम-उप निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम के द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 16 अक्टूबर बुधवार से, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराना 16 अक्टूबर बुधवार को, दावे या आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय 23 अक्टूबर बुधवार को अपरान्ह 3 बजे तक, दावे या आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर मंगलवार, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04 नवम्बर सोमवार, प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 8 नवम्बर शुक्रवार, दावे या आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश प्रारित होने के पांच दिवस के भीतर, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना 13 नवम्बर बुधवार तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना 16 नवम्बर शनिवार तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना 19 नवम्बर मंगलवार तक, निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 22 नवम्बर 2024 शुक्रवार को किया जाएगा। इसी तरह से पंचायत चुनाव के हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम के द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना 24 अक्टूबर गुरूवार से, दावे या आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय 29 अक्टूबर मंगलवार अपरान्ह 3 बजे तक, दावे या आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख 4 नवम्बर सोमवार, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 8 नवम्बर शुक्रवार, पारूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 14 नवम्बर गुरूवार, दावे-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना।

कबाड़ के तीन गोदामों में पुलिस ने की छापेमारी

11 वाहन जब्त, दो करोड़ बताई जा रही कबाड़ की कीमत

रायगढ़। रायगढ़ जिला मुख्यालय में सिटी कोतवाली एवं जूटमिल थाने की पुलिस टीम ने तीन अलग-अलग कबाड़ गोदामों में छापेमारी करते हुए स्क्रैप और आयरन पैलेट लोडेड 11 वाहनो को भी जब्त किया है। पुलिस के द्वारा पकड़े गए कबाड़ की कीमत 2 करोड़ रूपये बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कल शाम कोतवाली थाना एवं जूटमिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत तीन कबाड़ गोदामों पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि इन गोदामों में अवैध रूप से स्क्रैप और खनिज पदार्थों का भंडारण किया जा रहा है। सूचना के आधार पर ओड़ीसा रोड गढ़उमरिया, इंदिरा नगर जोगीडीपा, और ग्राम लाखा के कबाड़ गोदामों पर कार्रवाई की गई।

ओडिसा रोड के कबाड़ गोदाम पर छापा

जूटमिल पुलिस के साथ अधिकारियों ने ओड़ीसा रोड के ग्राम गढउमरिया स्थित कबाड़ गोदाम में दो प्राइवेट गार्ड मिले। गार्ड ने गोदाम को नाजिम अली का होना बताया। गोदाम परिसर के पास खड़े दो ट्रेलर में स्पंज आयरन (पायलट गोली), दो माजदा वाहन तथा 6 ट्रक (फुल डाला) में विभिन्न प्रकार के स्क्रेप जिसमें तार के टुकड़े, लोहे के कबाड़ लोड मिला। गोदाम में मौजूद व्यक्तियों ने वाहनों में लोड स्क्रैप के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर जूटमिल पुलिस ने 10 वाहनों को मय लगभग 200 टन कबाड के साथ कब्जे में लेकर पुलिस लाइन लाकर खड़ी किया गया है, संबंधित वाहन मालिक को दस्तावेज के साथ तलब किया गया है। वहीं गोदाम के संचालक को नोटिस जारी किया गया है।

इंदिरा नगर जोगीडीपा कबाड़ गोदाम में छापा

कोतवाली पुलिस ने शहर के भीतर इंदिरा नगर जोगीडीपा स्थित मो0 आरिफ के कबाड़ गोदाम में छापेमारी दौरान मो. आरिफ पिता हुसैन मोहम्मद मौजूद था। गोदाम के पास खड़ी एक पिकअप वाहन में स्क्रैप मिला, वाहन में ड्राइवर पिंटू यादव बैठा था, कबाड़ के संबंध में मोहम्मद आरिफ तथा ड्राइवर पिंटू यादव द्वारा कोई उपयुक्त जवाब नहीं दिए जाने पर पुलिस ने कबाड़ की मय पिकअप वाहन जप्ती की। जप्त अवैध कबाड़ का वजन करीब 1,500 किलो है, गोदाम संचालक मो0 आरिफ एवं वाहन चालक पिंटु यादव पर धारा 35(1)(ई) बीएनएसएस 303 बीएनएस के तहत कार्यवाही किया गया है।

पूंजीपथरा- लाखा कबाड़ गोदाम में छापा

कोतवाली पुलिस ने रायगढ़-पूंजीपथरा रोड लाखा स्थित कबाड़ के गोदाम पर छापेमारी की, जहां मौजूद मिले कर्मचारी ने गोदाम को सत्येंद्र विश्वकर्मा का होना बताया, सत्येंद्र विश्वकर्मा फरार है। पुलिस ने गोदाम पर नोटिस चस्पा कर कबाड़ गोदाम से करीब 2 टन 650 किलो कबाड़ की जप्ती की गई।

जारी किया गया नोटिस

पुलिस ने दो कबाड़ गोदाम संचालकों को नोटिस जारी कर दस्तावेजों सहित थाने तलब किया गया है। नोटिस के समयावधि में कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होता, तो पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

करंट से भालू और दो शावकों की हुई मौत

कांकेर। नरहरपुर वन परिक्षेत्र में देवी नवागांव के खेत में करंट की चपेट में आने से वन्य प्राणी मादा भालू और दो शावकों की मौत की मौत हो गई है। इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंचकर विभाग की टीम ने इलाके का निरीक्षण कर यह स्पष्ट किया कि, भालुओं की मौत हादसे में हुई है। डीएफओ आलोक बाजपाई ने बताया कि मौके पर वन विभाग की टीम की जांच में यहां किसी तरह का ट्रैप नहीं लगा था। हादसे में भालुओं की मौत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार खेत में बिजली के पोल से तार टूटकर गिरा था खेत में पानी भरा होने के कारण उसमे करंट फैल गया था। इसी दौरान बिजली के पोल से तार टूटकर गिर गया था। जिसकी चपेट में इलाके में विचरण कर रहे भालू आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग और बिजली विभाग की टीम ने इलाके का निरीक्षण करने के बाद स्पष्ट किया है कि यहां किसी तरह का ट्रैप नही लगाया गया था भालुओं की मौत एक हादसा है।

मक्का फसल के बीच गांजा का पौधा लगाने वाला गिरफ्तार

कोंड़ागांव। सीटी कोतवाली पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम बड़े घोड़सोड़ा के बुधराम सागर के द्वारा अपने मक्का बाड़ी में मक्का फसल के बीचो-बीच मादक पदार्थ गांजा का हरा पौधा लाभ कमाने के लिये लगाया है। सूचना पर आरोपी के मक्का बाड़ी की तलाशी लेने से आरोपी के कब्जे से 43 नग मादक पदार्थ गांजा जिसका कुल वजन 1.565 किलो बरमद किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 20 (क) नारकोटिक्स एक्ट का पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही उपरांत मौके पर गांजा पौधा को जप्त कर आरोपी बुधराम सागर पिता सुकुराम सागर उम्र 44 वर्ष जाति घसिया साकिन बड़े घोड़सोड़ा थाना अनतपुर को गिरफ्तार किया गया है। सम्पूर्ण कार्यावाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अखिलेश धीवर, सउनि. अभिराम मेश्राम, डोमन लाल दीवान, प्र.आर. 229 भूपेन्द्र मरकाम, प्रआर. 85 रघुनाथ कश्यप,भावेश मंडावी ,छबीराम कोर्राम,आरक्षक क्रमांक 472 घनश्याम भुआर्य, 955 मनराज वट्टी, डीएसएफ आर. 2044 चन्द्रहास मरकाम का योगदान रहा।

ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार तीन युवक

जगदलपुर। जगदलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आए दिन सड़क हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई। कोंड़ागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाइवे-30 पर भैरव मंदिर के पास बीती रात जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे ट्रक की चपेट में एक बाइक आ गई। जिसपर तीन युवक सवार थे, वे अचानक ट्रक के सामने आ गए। जिसके बाद ट्रक चालक के द्वारा बाइक सवार को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन ट्रक चालक सफल नही हो पाया और बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया। जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है तीन युवक एक बाइक पर सवार होकर फरसगांव से बोरगांव की ओर जा रहे थे, इसी दौरान उनकी बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

कार में अचानक लगी आग पूरे इलाके में मचा हड़कंप

गौरेला पेंड्रा मरवाही। पेंड्रा रोड़ रेलवे स्टेशन में उस समय हड़कंप गया जब स्टेशन परिसर में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग से कार के सामने का पूरा हिस्सा जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना के कुछ समय पहले ही कार सवार कार को खड़ा करके स्टेशन परिसर में ही मौजूद थे। आग लगने के तुरंत बाद आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग से कार का सामने का हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। जानकारी के अनुसार, कार सवार लगभग 11 बजे स्टेशन परिसर में पहुंचे और कार को स्टेशन परिसर में खड़ा कर पास ही खड़े हुए थे कि अचानक उनकी नजर कार पर पड़ी तो कार में आग लगी थी। जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से कार में लगी आग बुझाने का प्रयास किया गया। पर जब तक आग बुझी कार के सामने का हिस्सा जलकर खाक हो गया था। राहत की बात यह रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार कार में आग शार्ट सर्किट से लगने की बात सामने आ रही है।

बिलासपुर में अंतरराज्यीय देह व्यापार रैकट का भंडाफोड़

बिलासपुर। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय देह व्यापार करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मोपका के एक मकान में संदिग्ध अवस्था में 1 युवक व 8 युवतियां मिले। सभी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। दरअसल सरकंडा थाना क्षेत्रांतर्गत मोपका क्षेत्र में अवैध देह व्यापार की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी। इस पर सरकंडा पुलिस मुखबिर के माध्यम से तलाश में जुट गई। इसी बीच 8 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली कि मोपका के एक मकान में करीब 7-8 लड़कियां अलग अलग राज्यों से आई हुई हैं जो देहव्यापार में लिप्त है। इसकी सूचना पर सी.एस.पी सरकंडा सिद्धार्थ बघेल ने टीम तैयार कर मुखबिर के बताये घर पर रेड की। वहां एक मकान में एक युवक व 8 युवतियां संदिग्ध अवस्था में मिलीं। पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने लगीं। कड़ाई से पूछताछ करने पर देह व्यापार के लिए अन्य जगहों से आने की बात कही। 8 युवतियों में 2 उत्तर प्रदेश 1 पश्चिम बंगाल 1 मध्य प्रदेश और 4 छत्तीसगढ़ की हैं।

नारी सशक्तिकरण में टसर धागाकरण निभा रहा महत्वपूर्ण भूमिका

प्रीति अतिरिक्त आय अर्जित कर अपने सपने को कर रही है साकार

जशपुर। नारी सशक्तिकरण के माध्यम से एक सशक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने में ग्रामोद्योग संचालनालय की टसर धागाकरण योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जशपुर जिले में इस योजना के अंतर्गत कुमारी प्रीति चौहान जैसी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। कलेक्टर के मार्गदर्शन में प्रीति ने टसर धागाकरण का प्रशिक्षण प्राप्त किया और अब वह इस कार्य में अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। गरीब परिवार से आने वाली प्रीति आज अपने परिवार की आर्थिक मदद कर रही हैं और अपनी बचत से खेती में भी योगदान दे रही हैं। उनके खाते में अब तक 1 लाख 2 हजार रुपये से अधिक की राशि जमा हो चुकी है, जिससे उनका जीवनस्तर बेहतर हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुसार जशपुर जिले में धागाकरण प्रशिक्षण देकर समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें अपने गाँव में ही रोजगार मिल सके और उन्हें अन्य राज्यों की ओर रोजगार के लिए देखना न पड़े। टसर धागाकरण से जुड़ी अन्य महिलाएं भी अब गरीबी से उबरकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। इस योजना से उन्हें न केवल धागाकरण का कार्य मिला है, बल्कि वे अपनी कृषि भूमि पर खेती कर उन्नत किस्म का धान और अन्य फसलें भी उगा रही हैं। कई महिलाएं जो कभी साइकिल खरीदने का सपना देखती थीं, अब इस योजना से मिली आय से दोपहिया वाहन भी खरीद रही हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रही हैं।

रेशम विभाग द्वारा महिलाओं को कोकून बैंक के माध्यम से कोसा उपलब्ध कराया जाता है और उनके द्वारा उत्पादित धागे को विपणन कर उनकी आय को सीधे उनके खाते में जमा किया जाता है। इस प्रकार टसर धागाकरण योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है, जिससे न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रही हैं, बल्कि उनका समाज में एक अलग पहचान भी बन रही है। नारी सशक्तिकरण के इस प्रयास से महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने परिवार और समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

फल-फूल रहा ऑन लाइन सट्टे का अवैध कारोबार

बलौदाबाजार-भाटापारा। जिला बालौदा बाजार भाटापारा मे सट्टोरिए सक्रिय, नही पहुच पा रही पुलिस के मुखबीर सुचना तंत्र सट्टोरियो तक,जिला अतरिक्त पुलिस अधिक्षक ने अलग अलग थानो में कार्यवाही के निर्देश तथा मुखबीर होने की बात कह रहे है, जिले मे ऑन लाईन सट्टा, का कारोबारी दिन-दुगनी रात चैगुनी कर रहे है।

आप को बात दे की भाटापारा को सट्टा का गढ माना जाता है, जिला बलौदा बाजार भाटापारा से पुर्व मे बहुत से रसुखदारो को सट्टा खिलाने व खाईवाली करने के नाम से जेल जाना पडा है, लेकिन वर्तमान मे सट्टोरिए हाई टेक हो गए है, अलग अलग एप्प के माध्यम से सट्टे के कार्य को संचालित कर रहे है, जिला पुलिस सट्टे पर खाना पुर्ति कार्यवाही के लिए सट्टा पट्टी ,डाट पेन, व कुछ नगदी रूपऐ के साथ कभी कभी छोटे सटोरियो को जेल भेज देती है।

जब बात ऑन लाईन बडे सट्टोरिए, खाईवालो की होती है तो न पुलिस के आदेश निर्देश का पलान होते नजर आता है न ही मुखबीर की मुखबीरी। जिला बलौदा बाजार व भाटापारा मे आन लाईन सट्टा खेलने व खिलाने वाली एप्प आई डी खाईवालो से बच्चे, जवान, दस -दस हजार रूपए मे खिरीद कर सट्टे के कारोबार मे कुछ फल फुल रहे है तो नबालिक इस दलदल व्यापार मे बर्बाद हो रहे है। जब इस संबंध मे जिला अतरिक्त पुलिस अधिक्षक हेम सागर सिदार से बात की गई तो उन्हो ने कहा की जिले के सभी थानो मे कार्यवाही के लिए निर्देशीत किया गया है, तथा मुखबीर भी लगया गया है, सुचना प्राप्त होने पर कार्यवाही भी करने की बात कर रहे है जब जिला अतरिक्त पुलिस अधिक्षक हेम सागर सिदार से पुछा गया की क्या पुराने सट्टोरियो जो जेल काटकर बाहर निकल चुके है क्या उनपर भी पुलिस की नजर है ? तो उन्होने कहा की पुलिस टीम हर तरह से जॉच कर रही है संलिप्त पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री साय का गुरुवार 10 अक्टूबर को होने वाला जनदर्शन कार्यक्रम स्थगित

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गुरुवार 10 अक्टूबर को होने वाला जनदर्शन कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग ने दी है। अब अगले गुरुवार को सीएम साय के जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है।

वनमंत्री केदार कश्यप के ओएसडी बने काण्डे

रायपुर। प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के.एन. काण्डे को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जलसंसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी नियुक्त किया गया है। सहकारिता विभाग मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेश के तहत श्री के.एन. काण्डे को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग मंत्री के निजी स्थापना में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

नवरात्रि में रायपुर के रियल एस्टेट सेक्टर में बूम, 25 प्रतिशत अधिक रजिस्ट्री

रायपुर। इस वर्ष नवरात्रि में रायपुर जिले में रियल एस्टेट सेक्टर में काफी बूम देखने को मिल रहा है। इस बार नवरात्रि के दौरान तीन दिनों में एक हजार रजिस्ट्रियां हुई है, जो बीते साल नवरात्रि के शुरूआती तीन दिनों में हुई रजिस्ट्रियों से 25 फीसद से भी ज्यादा है। बीते वर्ष शारदीय नवरात्रि के शुरूआती तीन दिनों यानि 16,17 एवं 18 अक्टूबर को रायपुर जिले में कुल 796 दस्तावेज पंजीबद्ध हुए थे, जबकि इस साल नवरात्रि में 3, 4 और 7 अक्टूबर को पंजीबद्ध हुए दस्तावेजों की संख्या एक हजार है, जो कि बीते वर्ष की तुलना में 204 अधिक है। जिला पंजीयक रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार नवरात्रि में दस्तावेजों के पंजीयन से शासन को 14 करोड़ 6 लाख 96 हजार रूपए की आय प्राप्त हुई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 37 लाख 11 हजार रूपए अधिक है। बीते वर्ष इसी अवधि में 796 दस्तावेजों के पंजीयन से शासन को 13 करोड़ 69 लाख 85 हजार रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।

अम्बेडकर अस्पताल में दशहरे के दिन भी ओपी डी खुली रहेगी

रायपुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर से संबध्द डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में शनिवार 12 अक्टूबर को दशहरा (विजयादशमी पर्व) के दिन बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) का संचालन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूर्व की भांति होगा। विदित हो कि शुक्रवार को महानवमी पर्व हेतु स्थानीय अवकाश 12 अक्टूबर शनिवार को दशहरा पर्व हेतु सामान्य अवकाश तथा 13 अक्टूबर को रविवार होने के कारण निरंतर तीन दिवस के अवकाश होने के फलस्वरूप 12 अक्टूबर (शनिवार) को बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) का संचालन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा।

पेट्रोलिंग टीम ने अशांति फैलाने वाले आठ गुंडे-बदमाशों को किया गिरफ्तार

बिलासपुर। नवरात्रि त्योहार के मद्देनजर तारबाहर थाना की स्ट्रीट/ पैदल पेट्रोलिंग टीम ने अशांति फैलाने वाले 8 बदमाश- उपद्रवियों को पकड़ है। इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ पृथक-पृथक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। इसी क्रम में थाना तारबाहर से एक टीम थाना क्षेत्र में स्ट्रीट/ पैदल पेट्रोलिग के लिए रवाना की गई। टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान पुराना बस स्टैंड, देशी शराब भट्टी, राजीव कंपलेक्स के आसपास से उपद्रव और अशांति फैलाने वाले आठ लोगों की धर-पकड़ कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि अशांति फैलाने वाले गुंडा-बदमाश और असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का हो रहा चंहुमुखी विकास : साव

भारत सरकार द्वारा राज्य में 8 सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ रुपए स्वीकृत

- छत्तीसगढ़ में सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार का मिल रहा है लगातार सहयोग
- 6 जिलों में 324 किमी सड़क के विकास के लिए मंजूर की गई राशि

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने भारत सरकार द्वारा आठ सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास हो रहा है। राज्य में सड़कों के निर्माण में केंद्र सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने विगत 30 सितम्बर को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी थी।

राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के छह जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए इस साल 9 सितम्बर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल पर भारत सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में आठ राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए सीआरआईएफ से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सीआरआईएफ से मंजूर की गई इस राशि से बेमेतरा और मुंगेली जिले में नांदघाट-मुंगेली सड़क खंड और बेमेतरा-नवागढ़-मुंगेली सड़क खंड का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किया जाएगा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव-चौकी-मोहला मानपुर सड़क खंड, जशपुर जिले के बागबहार-कोतबा सड़क खंड, लुड़ेंग-तपकरा-लावाकेरा सड़क खंड और जशपुर-आस्टा-कुसमी सड़क खंड के मजबूतीकरण का कार्य भी इनमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी-सरवानी-पसीद-अमलडिहा-बरतोरी-दगोरी सड़क खंड तथा राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के राजनांदगांव-कवर्धा-पोंडी सड़क खंड के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य भी इस राशि से किया जाएगा।

जल जीवन मिशन से दूरस्थ ग्राम राजादेवरी की बदली तस्वीर

रायपुर। दूरस्थ वनांचल ग्रामों में जल जीवन मिशन पूरा होने से गांव की तस्वीर बदल रही है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कसडोल के दूरस्थ ग्राम राजादेवरी में अब लोगों को पीने के लिए घर में ही स्वच्छ जल मिलने लगा है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस मिशन का उद्देश्य हर घर तक नल द्वारा स्वच्छ और सुरक्षित पानी पहुँचाना है, जिससे ग्रामीण जीवन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। गांव वालों से चर्चा करते हुए जल जीवन मिशन के राजकुमार कोशले ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत, सिंगल विलेज योजना अन्तर्गत गांवों में नल-जल योजनाएं स्थापित की गई हैं, जिससे गांव के लोगों को स्वच्छ पानी प्राप्त हुआ है। स्वच्छ पानी की उपलब्धता से जल जनित बीमारियों में कमी आई है, जिससे ग्रामीणजनों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। पानी लाने में लगने वाला समय बचाने के कारण महिलाओं को अन्य कार्यों में भाग लेने का अवसर मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। मिशन के अंतर्गत जल संरक्षण और कुशल उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम सतत चलाए जा रहे हैं, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि जल जीवन मिशन ने न केवल पेयजल की समस्या का समाधान किया है, बल्कि यह ग्रामीण विकास और आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है।

179 महतारी सदन की मिली स्वीकृति 25 सौ वर्गफुट में बनेगा महतारी सदन

रायपुर। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के निर्देशानुसार महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयास से 179 महतारी सदन की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहा महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लगातार ग्राम भ्रमण के दौरान महिलाओं द्वारा बैठने की स्थान न होने की शिकायत की और बैठने हेतु स्थान दिलाने की मांग की जाती रही इसलिए महतारी सदन बनाने का विचार आया। ततपश्चात महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनको काम काज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार गांवों में महतारी सदन बनाने जा रही है। 179 महतारी सदन की स्वीकृति इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिये जारी किया गया है। कार्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया है। प्रति महतारी सदन की लागत राशि रुपये 29.20 लाख होगी। उक्त कार्य महतारी सदन योजना के बजट से 24.70 लाख तथा स्वच्छ भारत मिशन के बजट से 4.50 लाख के अभिसरण से किया जाएगा। इसप्रकार 179 महतारी सदन हेतु 52 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है।

प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाया जाएगा। महतारी सदन बनाने की शुरुआत हो गयी है। पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदन बनना प्रारंभ किया जा रहा है व 5 साल में सभी ग्राम पंचायत में महतारी सदन बनेंगे। प्रदेश में बनने वाले महतारी सदन का निर्माण लगभग 25 सौ वर्गफुट में कराया जाएगा। सदन में कमरा, शौचालय, बरामदा, हाल, किचन और स्टोररूम जह्यैसी सुविधाएं रहेगी। पानी के लिए ट्यूबवेल के साथ वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमे बॉउंड्रीवाल भी बनाये जाएंगे।

केदार ने हरियाणा में कांग्रेस के जलेबी ऑर्डर को लेकर कसा तंज

- कहा- शपथ ग्रहण समारोह में खिलाएंगे जलेबी

रायपुर। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भाजपा शानदार जीत की साथ सत्ता की 'हैट्रिक' लगाई है। रिजल्ट आने से पहले कांग्रेस ने जीत की उम्मीद के साथ जलेबी का ऑर्डर दिया था। इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए विपक्ष की कांग्रेस पार्टी को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 15 वर्षों से लगातार मिठाइयों को ऑर्डर दे रही है, लेकिन ऑर्डर उठा नहीं पा रही है। उनका काम नहीं चल पा रहा है, उनके नेता नहीं चल पा रहे हैं। इस बार भी उन्होंने जलेबी का आर्डर दिया था, लेकिन जलेबी भी नहीं चल पाई।

मंत्री कश्यप ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हम आमंत्रित करते हैं उनको (कांग्रेस को)। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में आए उस दिन उनको जलेबी खिलाएंगे। कांग्रेस के लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे थे कि अपना नाम बदल लेंगे अब पता नहीं कौन सा नाम रखेंगे।

पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर ली चुटकी

छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अमरजीत भगत ने भी हार पर मूंछ मुंडवाने का दावा किया था। इसे लेकर मंत्री केदार कश्यप ने चुटकी लेते हुए कहा कि मूंछ कटवाने की बात हुई थी, बाद में पता चला कि मूंछ छटवाया है। जिनकी मूंछ को जनता ने ही काट दिया है, वो तो अब मूंछ दिखाने के लायक भी नहीं रहे।

जम्मू-कश्मीर में हार को लेकर मंत्री कश्यप का बयान

वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर में आए परिणाम को लेकर कहा कि हमारा जो परफॉर्मेंस था, उससे वहां वोट प्रतिशत बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। आने वाले समय में बेहतर काम करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का ही अंग है। नरेंद्र मोदी की जो भी योजनाएं हैं उनका वहां कार्य नजर आया है।

रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

मंत्री कश्यप ने रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुने जाने को लेकर विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए देश में नेता खोजना मुश्किल हो चुका है। कांग्रेस के बड़े नेता ही सर दर्द बन चुके हैं।

छत्तीसगढ़ में सेक्स एजुकेशन को लेकर बयान

वहीं सेक्स एजुकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स एजुकेशन को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट मानना गलत है। इससे युवाओं में अनैतिकता नहीं बढ़ती। इसलिए भारत में इसकी शिक्षा बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ में सेक्स एजुकेशन को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारे बच्चों को गुड टच और बेड टच की जानकारी दी जाती है। इसे बेहतर और वृहद रूप में कैसे अच्छा करें, इस पर कार्य किया जाएगा।

वहीं छत्तीसगढ़ में महतारी सदन के निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है। इसे लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पंचायत मंत्री ने हमारी माता बहनों को सशक्त करने के लिए लगातार नई योजना बनाई है। निश्चित तौर पर माता बहनों के लिए कार्य किया है और इसी दिशा में महतारी सदन की भी स्वीकृति दी है।

डिप्टी सीएम शर्मा ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के धोए पैर

- नए आवास की चाबी और प्रमाण पत्र किया भेंट

कबीरधाम। बुधवार को कवर्धा विधायक और डिप्टी सीएम विजय शर्मा कबीरधाम जिले के दौरे पर हैं। मोदी की गारंटी में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज शक्ति के प्रतीक पवित्र नवरात्रि पर्व के मौके पर कवर्धा के इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक दिवसीय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला स्तरीय आवास मेला में शामिल हुए। जिले के 18 हजार से अधिक आवासहीन ग्रामीण परिवारों को उनके नए स्वीकृत हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृत पत्र वितरण कर सम्मानित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का पारंपरिक संस्कृति से चरण पखार (पैर धोकर) ग्रामीण परिवारों का सम्मान कर स्वागत किया।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने आवास मेले में कबीरधाम जिले के 12 हजार से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने नए आवास की चाबी और पूर्णता प्रमाण पत्र भेंट की। जिले में विगत कुछ ही समय में 12 हजार से अधिक पीएम आवास पूर्ण कर लिया गया है। शर्मा ने मेले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रशिक्षित 250 से अधिक राज मिस्त्री को प्रमाण पत्र और टूल किट का वितरण किया।

इस दौरान गुणवत्ता पूर्ण आवास निर्माण के लिए शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच, कर्मचारियों, संस्थाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जिले के असाक्षर को साक्षर बनाने के उद्देश्य अभ्यास पुस्तिका प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री ने आवास जागरूकता पर आधारित पोस्टर का विमोचन किया। आवास मेला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैंप, लीड बैंक द्वारा बैंकिंग सुविधाओं के लिए कैम्प और खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड आदि के लिए स्टॉल लगाया है।

झारसुगुड़ा से नागपुर तक चलने वाली ट्रेनों में लगेगा सुरक्षा कवच

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर सख्त नजर आ रहा है। नागपुर-रायपुर, बिलासपुर और झारसुगुड़ा के बीच चलने वाली ट्रेनों में सुरक्षा कवच लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके लिए जोन ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही ट्रेनों में कवच लगाने का काम शुरू हो जाएगा। रायपुर रेल मंडल के डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा कि झारसुगुड़ा से लेकर नागपुर क्षेत्र में चलने वाली ट्रेनों में सुरक्षा कवच लगाने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्दी यह लागू हो जाएगा। सुरक्षा कवच एक ही ट्रैक पर यदि दो ट्रेनें आ रही हैं तो उसे अलर्ट करेगा। सेंसर के जरिए ट्रेन के चालक और सह चालक को भी अलर्ट करेगा। कवच सिस्टम सेंसर के माध्यम से एक ही ट्रैक पर यदि दो ट्रेनें आ रही हैं तो उसे अलर्ट करेगा। सेंसर के जरिए ट्रेन के चालक और सह चालक को भी अलर्ट करेगा। साथ ही ट्रेनों की गति पर कवच सिस्टम खुद ही ब्रेक भी लगा देता है। इससे ट्रेन से होने वाले हादसों में कमी आएगी। घने कोहरे, बरसात जैसे मौसम में यदि लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो भी यह प्रणाली स्वचालित रूप से गति को नियंत्रित करने में मदद करती है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर मंडल, बिलासपुर

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना
Portal : http://eproc.cgstate.gov.in

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर में निम्नलिखित कार्य नवीन ई-पंजीयन में पंजीकृत ठेकेदार दिनांक 24.10.2024 तक निविदा आमंत्रित की जाती है-

क्र.	नि.आ.सू. क्र. / दिनांक	कार्य का नाम	लागत (लाख में)
1	193	उपसंभाग क्र. -2, बिलासपुर के सीपत उपखण्ड के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में रंगाई पोताई, डिस्टेंपरिंग का कार्य। प्रथम आमंत्रण। संभाग क्र . 1, बिलासपुर।	25.00
2	194	उपसंभाग क्र. -2, बिलासपुर के मस्तूरी उपखण्ड के अंतर्गत् आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में मरम्मत कार्य। प्रथम आमंत्रण। संभाग क्र. 1, बिलासपुर।	25.00
3	195	उपसंभाग क्र. 2, बिलासपुर के जजेस कॉलोनी के अंतर्गत आवासीय भवनों में रंगाई पोताइ एवं डिस्टेंपरिंग कार्य। प्रथम आमंत्रण। संभाग क्र. 1. बिलासपुर।	25.00
4	196	पसरवारा से नारायणपुर तक पहुंच मार्ग लंबाई 1.875 कि.मी. का निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण। मुंगेली संभाग।	190.98
5	197	देवरहट से हरनाचाका तक पहुंच मार्ग लंबाई 1.75 कि.मी. का निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण। मुंगेली संभाग।	168.75
6	198	बैजलपुर से बोदोफाल पहुंच मार्ग लंबाई 1.20 कि.मी. का निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण। मुंगेली संभाग।	133.02
7	199	धोबघट्टी से बस्ती तक पहुंच मार्ग लंबाई 1.50 कि.मी. का निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण। मुंगेली संभाग।	189.59
8	200	बघमार से अमलडीहा बस्ती तक पहुंच मार्ग लंबाई 0.625 कि.मी. का निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण। मुंगेली संभाग।	64.38
9	201	भटलीखुर्द (सेमरसल) से बहटा मार्ग लंबाई 1.10 कि.मी. का निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण। मुंगेली संभाग।	132.46
10	202	गैजी गांव से चितावर तक पहुंच मार्ग लंबाई 1.735 कि.मी. का निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण। मुंगेली संभाग।	177.33
11	203	जिला न्यायालय भवन जांजगीर चांपा में मरम्मत कार्य। प्रथम आमंत्रण। चांपा संभाग।	52.50
12	204	जिला न्यायालय भवन जांजगीर चांपा में बार रूम, हॉल, लाईब्रेरी, मीटिंग हॉल एवं नजारत के साथ स्टोर रूम और कोर्ट हॉल का निर्माण कार्य। प्रथम आमंत्रण। चांपा संभाग।	103.46
13	205	सक्ती उपसंभाग के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में साधारण मरम्मत कार्य। प्रथम आमंत्रण। चांपा संभाग।	39.73
14	206	रायगढ़ उपसंभाग के अंतर्गत् विभिन्न मार्गों में डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. पेच मरम्मत का कार्य। प्रथम आमंत्रण। रायगढ़ संभाग।	79.80
15	207	रायगढ़ उपसंभाग के अंतर्गत् तमनार, हमीरपुर सेक्शन 1, 2 एवं महापल्ली सेक्शन में डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. पेच मरम्मत का कार्य। प्रथम आमंत्रण। रायगढ़ संभाग।	40.00
16	208	धरमजयगढ़ उपसंभाग के अंतर्गत् धरमजयगढ़ एवं कापू सेक्शन के विभिन्न मार्गों में डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. पेच मरम्मत का कार्य। प्रथम आमंत्रण। रायगढ़ संभाग।	66.91
17	209	रायगढ़ उपसंभाग के अंतर्गत् पुसौर सेक्शन के विभिन्न मार्गों में डब्ल्यू.एम.एम. एवं बी.टी. पेच मरम्मत का कार्य। प्रथम आमंत्रण। रायगढ़ संभाग।	40.00
18	210	रायगढ़ उपसंभाग के व्ही.आई.पी. भवनों, सामान्य प्रशासन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में साधारण मरम्मत का कार्य। प्रथम आमंत्रण। रायगढ़ संभाग।	32.00

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखें जा सकते है।

अधीक्षण अभियंता
लो.नि.वि.बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर

जी-242503009/9

राजस्व अभिलेखों के पुराने रिकॉर्डों का होगा डिजिटलाइजेशन

- सड़क दुर्घटना रोकने के लिए आवारा मवेशियों के रंगे जाएंगे सींग

रायपुर। रायपुर जिले की प्रभारी सचिव और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारीक ने कलेक्टोरेट परिसर के रेडक्रॉस सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा की। इस दौरान प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की आजीवन सदस्य बनीं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की उपस्थिति में आयोजित विभागीय समीक्षा में प्रत्येक विभागों के कार्यों की प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने जानकारी ली और लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने कहा कि राजस्व अभिलेखों के पुराने रिकॉर्ड को सुरक्षित किया जाएं। इसके लिए पुराने अभिलेखों को डिजिटलाइजेशन किया जाएं। इससे सभी दस्तावेज हमेशा के लिए सुरक्षित होंगे। सभी सक्षम अधिकारी समय-समय पर राजस्व के लंबित प्रकरणों की मॉनीटरिंग कर उसका निपटारा करें। उन्होंने कहा कि जिले के मुख्य मार्गों में होने वाले सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। सड़कों पर बैठे मवेशियों की वजह से होने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए पशुधन विभाग को आवारा मवेशियों के सींग में गुणवत्तायुक्त रंग लगाने के निर्देश दिए। इससे वाहनों चालकों को रात के अंधेरे में दूर से ही सड़कों पर बैठे मवेशी आसान से नजर आएं। साथ ही कॉलर बेल्ट भी पहनाया जाएं। मवेशियों के बैठने के लिए चबूतरा बनाया जाएं और गांवों में चौपाल लगाकर मवेशियों को सड़क से हटाने के लिए जागरूक किया जाए।

बारिश का पानी कहीं पर भी किसी भी स्थिति में न भरें, इसका विशेष ध्यान रखा जाएं। प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं में समस्या आने पर आम नागरिकों से फीडबैक लिया जाएं और उनकी समस्याओं को त्वरित निराकृत किया जाएं। समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह ने जिले में नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने बताया कि गांजा की तस्करी रोकने के लिए पड़ोसी राज्य ओड़िसा के करीब में चेकपोस्ट लगाया गया है, जहां पर वाहनों की समय-समय पर जांच की जाती है, ताकि रायपुर शहर तक मादक पदार्थ न पहुंचे। प्रभारी सचिव श्री बारीक ने कहा कि बच्चों और युवाओं को नशे की लत से दूर किया जाएं। नशा मुक्ति केंद्र में वर्तमान में 15 बिस्तरों की संख्या को बढ़ाई जाएं और वहां युवाओं की काउंसिलिंग बेहतर की जाएं। श्रीमती बारीक ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं पेयजल, साफ-सफाई के लिए किसी भी आम नागरिकों को परेशानी न हो और असुविधा होने पर फीडबैक लिया जाए और समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएं। श्रीमती बारीक ने कहा कि अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएं और शराब दुकानों में शराब की ओव्हररेट बिक्री करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएं। इसके अलावा प्रभारी सचिव ने मत्सय पालन, मनरेगा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, पीएम सूर्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नल-जल योजना, अमृत सरोवर, समाज कल्याण विभाग, आईटीएमएस, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, स्कूल शिक्षा विभाग समेत विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की।

समाचार पचीसा
रायपुर, गुरुवार 10 अक्टूबर 2024

जम्मू-कश्मीर के नतीजों के निहितार्थ

उमेश चतुर्वेदी

माना जा रहा था कि जम्मू इलाके की 43 सीटों में ज्यादातर भाजपा जीतेगी, पर वह 29 सीटें ही जीत पायी। उसे 14 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। वैसे भाजपा का एक धड़ा मान रहा है कि पार्टी की आपसी गुटबाजी और गलत टिकट बंटवारा सफलता की राह में बाधा बन गयी। पार्टी के लिए संतोष की बात यह भी है कि घाटी की कई सीटों पर उसके उम्मीदवार हजार-दो हजार वोटों के ही अंतर से हारे हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य एवं राम मंदिर में क्या कोई समानता हो सकती है? मोटे तौर पर देखें, तो नहीं हो सकती। लेकिन जब भाजपा के संदर्भ में दोनों को देखें, तो समानता नजर आती है। राममंदिर और जम्मू-कश्मीर भाजपा के मुख्य मुद्दे रहे हैं। लेकिन चुनावी मोर्चे पर दोनों ही मुद्दे कम से कम स्थानीय स्तर पर भाजपा को निराश ही करते रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 और कैबिनेट के प्रस्ताव 35ए की वजह से जम्मू-कश्मीर की स्थिति अन्य राज्यों से अलग रही है। यह स्थिति ही वहां के अलगाववाद के नासूर का कारण मानी जाती रही है। भाजपा ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर एक तरह से इस नासूर को ही खत्म कर दिया। ऐसे में इसका चुनावी श्रेय पार्टी को मिलने की उम्मीद होना स्वाभाविक है। लेकिन विधानसभा चुनाव नतीजों ने पार्टी को निराश ही किया है। यहां पर राममंदिर आंदोलन और उस बीच हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव की याद आना स्वाभाविक है। छह दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद अव्वल तो होना चाहिए था कि आगामी चुनाव में भाजपा को अपने दम पर जीत मिलती। पर 1993 के चुनाव में वह सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से दूर रही। जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राममंदिर बनकर तैयार हो गया। देश और दुनिया में इसे लेकर अलग तरह का उत्साह देखा गया। इसका चुनाव में फायदा मिलना चाहिए था। लेकिन उलटबांसी देखिए कि कुछ ही महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या वाली फैजाबाद सीट भाजपा हार गयी। इस कड़ी में मुख्य मुद्दे से जुड़े जम्मू-कश्मीर में भाजपा को चुनावी बढ़त न मिलना तीसरा झटका कहा जा सकता है। वहां जिस नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिला है, उसका चुनावी वादा है कि राज्य की पुरानी स्थिति बहाल करेंगे, यानी अनुच्छेद 370 को फिर से प्रभावी बनायेंगे। यह बात और है कि यह बहाली जम्मू-कश्मीर की आधी-अधूरी विधानसभा के वश की बात नहीं है। पर इस जीत के जरिये गठबंधन नैतिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश तो जरूर ही करेगा। इसका उसे राष्ट्रीय फायदा भले न मिले, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में काबिज भाजपा के लिए परेशानी खड़ी करने का जरिया वह बनाता रहेगा। वैसे भी भारत की राजनीति आज जिस मुकाम पर है, उसमें दलों को सिर्फ अपने सियासी स्वार्थ की चिंता है। उनकी प्राथमिकता में राष्ट्र बाद में आता है। इसलिए अंदरूनी मुद्दों को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछालने में दलों को कोई हिचक नहीं होती। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लंदन और अमेरिका के भाषण इसके उदाहरण हैं। दुनिया में भारत का दबदबा भले बढ़ रहा हो, भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था भले हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ ताकतें ऐसी भी हैं, जो भारत में उथल-पुथल देखना चाहती हैं। इसके लिए वे प्रयास भी करती रहती हैं। जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन की जीत को ये ताकतें बहाना बनायेंगी और यह नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश करेंगी कि जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति उसकी अवाम को ही स्वीकार्य नहीं है। इस बहाने घूम-फिर कर उसी तर्क को बढ़ावा दिया जायेगा, जो पाकिस्तान देता रहा है तथा जिसकी वकालत नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे दल भी करते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में भाजपा को चुनावी जीत न मिलने के बाद वे फिर उसके नजरिये को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। कश्मीर घाटी में नवगठित विधानसभा की 47 सीटें आती हैं, जबकि जम्मू इलाके में 43 सीटें हैं। घाटी की सीटों पर भाजपा चुनावी संभावनाओं की कोई उम्मीद भी नहीं लगायी हुई थी। वैसे भी घाटी की 28 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी नहीं दिये थे।

भाजपा का नया गढ़ हरियाणा और कश्मीर में लोकतंत्र की वापसी

अजय बोकिल

लोकसभा चुनाव के ठीक चार महीने बाद हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों से कुछ संकेत साफ हैं। पहला तो यह कि देश में गुजरात और मध्यप्रदेश के बाद हरियाणा ऐसा राज्य बन गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। यानी उत्तर भारत में हरियाणा भाजपा का नया मजबूत किला बन गया है।

नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उस भविष्यवाणी को भी हकीकत में बदल किया कि हरियाणा में कांग्रेस का हश्र मध्यप्रदेश जैसा ही होगा, वैसा हुआ भी। दूसरा, लोस चुनाव के नतीजों से सबक लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति में कई बदलाव किए, जिसमें टिकटों के बंटवारे से लेकर बाहरी नेताओं का समावेश और वोटों का प्रति जाट ध्रुवीकरण शामिल है।

नतीजों ने यह भी साबित किया कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने किसान, जवान और पहलवान का जो नरेटिव सेट किया था, वह सतही था। राज्य में ओबीसी जातियों का यह डर भाजपा के पक्ष में काम कर गया कि यदि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो जाटों की दबंगई फिर शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो दलित लोस चुनाव में कांग्रेस की तरफ बड़े पैमाने पर चले गए थे, वो इस बार बंट गए और फायदा भाजपा को मिला।

यही स्थिति जाट वोटों की भी रही। इसके विपरीत कांग्रेस की कोई सुस्पष्ट रणनीति नहीं दिखी, सिवाय इस भरोसे के कि जनता इस बार उसे जिताने के लिए तैयार बैठी है। दूसरे राज्य के प्रभावशाली और मुखर जाट समुदाय की नाराजी को जनता की नाराजी मान लेना भी गलती थी।

कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण बचाने तथा जाति जनगणना का जो नरेटिव कुछ राज्यों में जबर्दस्त ढंग से काम कर गया था, वो इन विधानसभा चुनाव में फेल रहा। इन नतीजों का कांग्रेस के लिए सबक यह है कि अगर राज्यों में किसी एक नेता पर आंख मूंद कर भरोसा कर कमान उसके हाथ में देने और बाकी की उपेक्षा की जाए तो खेल बिगड़ जाता है।

यह हम इसके पहले मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में देख चुके हैं, जहां पार्टी ने क्रमश- कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल पर असंदिग्ध भरोसा किया और हाथ आती सत्ता फिसल गई।

इन परिणामों का कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के लिए बड़ा सबक यह है कि जब तक वो संगठन को ऊपर से नीचे तक नहीं कसेंगे, उसमें लडाकू तेवर पैदा नहीं करेंगे, तब तक छुटपुट सफलताओं से ज्यादा हासिल कुछ नहीं होगा। मोदी और भाजपा को हिलाना इतना आसान नहीं है।

लोस में भाजपा द्वारा संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने वाला दांव विधानसभा चुनावों में इस नहीं चल पाया, क्योंकि वो नरेटिव एक आशंका पर ज्यादा आधारित था। हकीकत में वैसा कुछ हुआ नहीं और शायद होगा भी नहीं।

हरियाणा विस चुनाव के नतीजे काफी कुछ 2023 में हुए मप्र विस चुनाव से मिलते हैं। मप्र में भी कांग्रेस माने बैठी थी कि जनता उसे ही जिताने वाली है। यहां तक कि जीतने के बाद कौन क्या बनेगा, यह भी एडवांस में तय हो गया था। पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस की बढ़त को पार्टी ने कुछ देर के लिए पूरा सच मान लिया। जबकि भाजपा ने बूथ मैनेजमेंट, लाडली बहना योजना और अपनी सफल चुनावी रणनीति से कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया। कुछ ऐसा ही हरियाणा में होता दिख रहा है।

भाजपा सरकार के प्रति 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद लोस चुनाव से पहले ओबीसी नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर पार्टी ने जहां लोस चुनाव में हुए राजनीतिक नुकसान को कम किया, वहीं विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार कर दी।

खास बात यह है कि हरियाणा में विस चुनाव के पहले भाजपा ने ऐसी कोई बड़ी रेवड़ी भी नहीं बांटी, जैसे कि मप्र में बांटी थी। भाजपा की रणनीति साफ थी कि प्रभावशाली जाट वोटों का बंटवारा करो और एंटी जाट वोटों को भाजपा के पक्ष में गोलबंद करो। वही होता दिख भी रहा है। पार्टी ने न केवल अपना वोट बैंक बचाया बल्कि उस जाट लैंड में भी सेंध लगा दी, जहां से कांग्रेस बंपर समर्थन की उम्मीद लगाए हुए थी।

हरियाणा के यादव बहुल अहीरवाल अंचल में भाजपा की भारी जीत के पीछे भाजपा द्वारा मप्र में एक यादव डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना भी बड़ा कारण हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बेरोजगारी, किसान आंदोलन, अग्निवीर जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वोटर इन मुद्दों पर अपनी राय लोस चुनाव में पहले ही व्यक्त कर चुका था।

अति आत्मविश्वास भी कांग्रेस को ले डूबा। हालांकि यह कहना कठिन है कि अगर वो दूसरी जाट पार्टियों और आप के साथ गठबंधन करती तो नतीजे बदल सकते थे। लेकिन चुनाव के दौरान दलित नेता कुमारी सैलजा की नाराजी कांग्रेस को डुबो गई। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने सैलजा को मनाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

सत्ता पाने से ही सीएम पद की लड़ाई का जनता में गलत संदेश गया। वैसे यह लड़ाई भाजपा में भी दिखी। वहां अनिल विज ने सीएम पद की दावेदारी ठोक दी थी, लेकिन उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। यह तय है कि सीएम का ताज नायब सिंह सैनी को मिलेगा। यानी मप्र की तर्ज पर भाजपा हरियाणा में फिर ओबीसी कार्ड ही खेलेगी।

उधर जम्मू-कश्मीर में भाजपा का सरकार बनाने का सपना दूर की कौड़ी ही था। वहां चुनाव जीतते ही सत्ता में आ रहे नेशनल कांफ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के नेता फारूख अब्दुल्ला ने कहा कि यह जनादेश राज्य से धारा 370 व 35ए हटाने और भाजपा के खिलाफ है। इससे स्पष्ट हो गया कि जम्मू कश्मीर में आगे भी टकराव की राजनीति होने वाली है।

इस मामले में कांग्रेस दुविधा में रहेगी, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मुद्दे पर चुप है, लेकिन प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की हामी है। दरअसल बीजेपी प्रदेश में शांति, अमन, पर्यटन को बढ़ावा जैसे मुद्दों पर घाटी में भी समर्थन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मुसलमानों में भाजपा के प्रति जो नाराजी है, वह खत्म नहीं हुई है।

अलबत्ता 2014 के विधानसभा चुनाव की तुलना में राज्य में बीजेपी की सीटें और वोट दोनों बढ़े हैं। लेकिन बीजेपी के साथ कभी सरकार बनाने वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का सफाया और भाजपा ने घाटी में निर्दलियों के समर्थन से सरकार बना सकने की संभावना पर नतीजो ने पानी फेर दिया है। अच्छी बात यह है कि जम्मू-कश्मीर के मतदाताओ ने अलगाववादी निर्दलीयों और अन्य पार्टियों को चुनने की जगह नेकां-कांग्रेस गठबंधन को समर्थन दिया। जिससे सरकार पांच साल तक चलने की उम्मीद ज्यादा है।

धारा 370 हटाने का दांव भी फेल

धारा 370 हटाने की मांग नेकां के घोषणा पत्र में जरूर है, लेकिन उसे भी पता है कि यह अब व्यावहारिक नहीं है। लिहाजा उसका जोर पूर्ण राज्य के दर्जे पर ही ज्यादा रहेगा। वैसे भी केन्द्र की मदद के बगैर जम्मू- कश्मीर में सरकार चलाना नामुमकिन है। हालांकि वहां भाजपा के सरकार न बना पाने से यह संदेश दुनिया में जरूर गया है कि राज्य के लोग अभी भी धारा 370 हटाने से खुश नहीं हैं और इसके अलग-अलग कारण हैं।

अलबत्ता सकारात्मक संदेश यह है कि आंतकवाद से प्रभावित इस राज्य में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हए हैं और लोकतंत्र मजबूत हआ है। अहम बात यह है कि जो तत्व कभी भारतीय संविधान और चुनावों को ही नकारते थे, वो मजबूरी में ही सही पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लौट रहे हैं। एक बात साफ है कि राज्य में जो संवैधानिक बदलाव किए गए हैं, उसका राजनीतिक और सामाजिक असर भी हमे जल्द दिखाई देगा। इस बात की संभावना कम है कि जम्मू कश्मीर की अवाम आए दिन आंतकी हमलों, पत्थरबाजी और बंद के दौर में लौटना चाहेगी। इन नतीजों ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर फिर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जम्मू कश्मीर में तो नतीजों सर्वे के हिसाब से आए हैं, लेकिन हरियाणा में तमाम सर्वे फेल हुए हैं। राजनेताओं को भी समझ आ गया है कि सर्वे के आधार पर मन में लड्डू भले फूट रहे हों, लेकिन हकीकत में पूरे नतीजे आने के बाद ही लड्डू खाना और बांटना चाहिए।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्याय:

गतांक से आगे...

परन्तु जिस रूप में जिस आकार में, जिस सांचे में, जिस प्रमाण में, जिस लिपि रूप में और जिस संख्या में आज वे वाजार में मिलते हैं क्या उसी रंग में और उसी ढंग में सदा से चले आते हैं? तथा निराकार बाबा ने अथवा ब्रह्मा दादा ने कपड़े की जिल्द में बन्धे बन्धाए, और आर्टपेपर पर सुनहरी अक्षरों में छपे छपाए हो ये ग्रन्थ लाईब्रेरियों की अलमारियों में चुपके से रख छोड़े हैं क्या? कोई भी बुद्धिमान् पुरुष उपर्युक्त प्रश्नों का जवाब हाँ में नहीं दे सकता।

प्राय: सभी जानते हैं कि कल से पहिले टाइप के छापेखाने नहीं थे परसों लीथो के पत्थरों और कागजों का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तरसों ताड़ के पत्तों को खोद लेने की व्यवस्था भी नहीं थी। इससे पूर्व किसी अतीत काल में लिपि प्रणाली के अभाव को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा।

यह हो सकता है कि हम अक्षर-समाम्नाय और लिपि-प्रणाली का आरम्भ वर्तमान गवेषकों की अपेक्षा लाखों या करोड़ों वर्ष पूर्व मानें परन्तु आखिर कभी न कभी तो आरम्भकाल मानना ही पड़ेगा! तो फिर उससे पूर्व उक्त ग्रन्थ किस रूप में थे ? और इससे भी पूर्व पूर्व यहाँ तक कि जब कभी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ होगा तब ये किस रूप में थे ? यह है एक समस्या जिसे समझ लेना प्रत्येक आस्तिक का काम है।

वेदों की उपर्युक्त परम्परा के समझ में आ जाने पर पुराणों की परम्परा का भी अपने आप बोध हो जायेगा, एतदर्थ इस अध्याय में सृष्टि के उत्पत्तिकाल से आरम्भ करके वर्तमान कलियुग के प्रवेश समय तक वैदिक-साहित्य अपने मौलिकरूप से किस प्रकार वर्तमान रूप में परिणत हुआ है, यह दिखाया जाता है।

महाप्रलय के बाद ब्रह्मा का प्रादुर्भाव- एक समय था जब कि यह दृश्य जगत् अनन्त में लीन था।

क्रमश: ...

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस : शरीर से ज्यादा मन को स्वस्थ बनाना जरूरी

ललित गर्ग

प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है और समर्थन जुटाना है। मानव समुदाय को तनावरहित जीवन देकर अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त करने में मदद करना भी इस दिन का ध्येय है। वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक क्रांति, बढ़ती हुई आबादी, शहरीकरण, महंगाई, बेरोजगारी एवं आधुनिक जीवन के तनावपूर्ण वातावरण के कारण मानसिक रोगों में भारी वृद्धि हुई है। यह किसी एक राष्ट्र के लिये नहीं, समूचे विश्व के लिये चिन्ता का विषय हैं। आज जीवन का हर क्षेत्र समस्याओं से घिरा है, आपाधापी एवं घटनाबहुल जीवन के कारण तनाव एवं दबाव महसूस किया जा रहा है, चाहे वह काम हो, रिश्ते हों, जीवन से उम्मीदें हों। हर आदमी संदेह, अंतर्द्वन्द्व और मानसिक उथल-पुथल की जिन्दगी जीने को विवश है। इन जटिल से जटिलतर होते हालातों में अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना महत्वपूर्ण हो गया है।

हर व्यक्ति जितना शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है, उससे ज्यादा वह मानसिक बीमारियों एवं विकारों से ग्रस्त है। शास्त्रों में कहा गया है- चिंता, चिता के समान है। प्रतिदिन के तनाव से उपजती और मौत के मुंह में ले जाती गंभीर बीमारियों को देखते हुए यह बात बिल्कुल सही साबित होती है। हर एक मिनट का हिसाब रखती, भागदौड़ भरी वर्तमान जीवनशैली में सबसे बड़ी और लगातार उभरती हुई समस्या है मानसिक तनाव। हर किसी के जीवन में स्थाई रूप से अपने पांव पसार चुका तनाव, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। निजी जिंदगी से शुरू होने वाला मानसिक तनाव पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या बना है, जो अपने साथ कई तरह की अन्य समस्याओं को जन्म देने में सक्षम है। यही कारण है, कि इसे बचने के लिए और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए योग, ध्यान, अध्यात्म और कई तरह के अलग-अलग तरीकों को लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक नया विश्लेषण दर्शाता है कि दुनिया भर में क़रीब एक अरब लोग मानसिक विकार के किसी ना किसी रूप से पीड़ित हैं। एक अध्ययन के अनुसार अकेले भारतवर्ष में ही लगभग पांच करोड़ से अधिक लोग मनोरोगी हैं। एक मानसशास्त्रीय रिपोर्ट का निष्कर्ष है-किसी भी जनसंख्या का डेढ़ प्रतिशत जीवन भर मानसिक बीमारी से ग्रस्त रहता है। दस प्रतिशत व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। मानसविदों की नवीनतम खोजों का सार है, संपूर्ण विश्व में हर दूसरा आदमी मानसिक दृष्टि से बीमार है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है, जाने-अनजाने प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी मनोरोग से सदा पीड़ित रहता है। चिंता, घबराहट, नींद की कमी, निराशा, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक सोच-ये सब मनोरोग के स्थूल लक्षण हैं। यह मानसिक पंगुता की शुरुआत है। इससे मस्तिष्क कुंठित हो जाता है।

हरियाणा : जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है

नीरजा चौधरी

चुनाव को संचालित करने में राजनीतिक दलों की अपनी जगह है, लेकिन हरियाणा के चुनावी नतीजे गवाह हैं कि आज जनता अपने ढंग से चुनाव लड़ रही है। जाट बनाम गैर जाट की लड़ाई तो हरियाणा में जमाने से है। लेकिन अब दलित मतदाता भी मुखर हैं, क्योंकि उन्हें अपने वोट की ताकत का अंदाजा हो गया है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए थे, उन सबने कांग्रेस के प्रचंड बहुमत से जीतने के अनुमान व्यक्त किए थे। लोगों को उन अनुमानों पर भरोसा भी हो रहा था, क्योंकि भाजपा दो कार्यकाल से वहां सत्ता में है। ऐसे में सत्ता विरोधी रुझान होना स्वाभाविक है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण युवा परेशान हैं। लोग बात कर रहे थे कि इस बार जनता सत्ता परिवर्तन के लिए मतदान करेगी। हालांकि शहरी क्षेत्रों में भाजपा के लिए समर्थन बरकरार था। इसके बावजूद चुनावी नतीजों का बिल्कुल उलट जाना और कांग्रेस के बजाय भारतीय जनता पार्टी का लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता पर काबिज होना वाकई एक बड़ी बात है। ऐसा भी नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही। भाजपा को बिल्कुल स्पष्ट बहुमत मिला है।

हरियाणा में कहा जाता था कि आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बन पाई है, ऐसे में हरियाणा जैसे राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा का सरकार बनाना बहुत मायने रखता है। अभी तक गुजरात और मध्य प्रदेश में ऐसा देखा गया था, लेकिन इस बार हरियाणा में भी भाजपा ने इतिहास रच दिया है। इसके बावजूद कि लोगों की नाराजगी को देखते हुए पार्टी आलाकमान ने मनोहर लाल को हटा दिया और उनकी जगह पर कुछ महीने के लिए नायब सैनी को लाया गया और दलित कार्ड खेला गया, क्योंकि भाजपा नेतृत्व को सत्ता जाने का डर सता रहा था। लेकिन जैसा कि हर बार भाजपा चुनाव में करती है, इस बार भी दिग्गज पार्टी नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री खुद ज्यादा नहीं गए, लेकिन बाकी नेता लगातार राज्य में प्रचार कर रहे थे। ऐसा नतीजा तब आया है, जब जाट वोट बंटा नहीं है। वैसे हरियाणा में आम तौर पर जाट वोट बंटता रहा है, लेकिन इस बार जाट वोट पूरी तरह?कांग्रेस के पाले में था और वे मुखर तथा आक्रामक थे। इसकी कई वजहें रही हैं, मसलन किसान आंदोलन, हरियाणा के पहलवानों के प्रति उदासीन रवैया आदि। इसके अलावा, पिछले दस साल से कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना था और जाटों के हाथ से राजनीतिक शक्ति छीन ली गई थी, इसलिए भी जाट भाजपा से नाराज थे।

कहा जा रहा है कि जाट बहुल क्षेत्रों में भी कई सीटों पर भाजपा आगे रही है। इसका मतलब है कि सिर्फ जाट वोटों का ही कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकरण नहीं हुआ, बल्कि गैर-जाट वोटों का भी भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ है। इसके अतिरिक्त, आखिरी दिनों में दलित और ओबीसी मतदाताओं ने भाजपा की तरफ रुख किया है, विशेष रूप से दलितों ने, जिसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था और जिसके चलते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पांच सीटें मिली थीं। भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसकी वजह है डर। मैं जब दलित बस्तियों में घूम रही थी, तो वहां दलितों ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो उसे गैर जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वे तो यहां तक कह रहे थे कि अगर कुमारी सैलजा को नहीं बनाते हैं, तो उदयभान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या अशोक तंवर को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी दलित हैं, जबकि अशोक तंवर तो उस दिन दो घंटे पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे।

उन्होंने बताया कि उन्हें डर है कि कांग्रेस के जीतने पर जाटशाही वापस आ जाएगी। यह डर इस उलटफेर की एक वजह हो सकती है, हालांकि हरियाणा चुनाव के नतीजे का बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है,?बहुत से लोग मान रहे थे कि यह परिवर्तन का चुनाव है, क्योंकि लोग बदलाव की बात कर रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां सत्ता विरोधी रुझान थे। जाट बनाम गैर जाट ध्रुवीकरण कई जमाने से हरियाणा में होता आया है। लेकिन इस बार जाट का ध्रुवीकरण मुखर था, जबकि गैर-जाटों का ध्रुवीकरण चुपचाप हुआ। और यह ध्रुवीकरण इतना व्यापक हुआ कि इसने ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रभावित किया।

आखिर इस जनादेश के जरिये हरियाणा की जनता क्या संदेश देना चाह रही है? दलित मतदाता मुखर हो रहे हैं। वे नहीं चाहते कि उन्हें अब पहले की तरह उत्पीड़ित किया जाए। उन्हें अपने वोट की ताकत का एहसास हो गया है। उन्होंने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने कांग्रेस का रुख किया, तो भाजपा अल्पमत में आ गई। अन्य कारण भी थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा के अल्पमत में आने का मुख्य कारण यही था कि दलित मतदाता कांग्रेस की तरफ झुक गए थे, और हरियाणा में दलित फिर भाजपा के खेमे में चले गए। कहने का मतलब है कि दलित और ओबीसी मतदाताओं को आप आज के समय में हल्के में नहीं ले सकते। चुनाव को संचालित करने में राजनीतिक दलों की अपनी जगह है, लेकिन आज जनता चुनाव को अपने ढंग से संचालित कर रही है।

मुझे ऐसा लगता है कि जाट ने कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाई, तो दलित-ओबीसी ने हवा का रुख भाजपा की तरफ घुमा दिया। मैं मानती हूं कि हुड्डा और सैलजा के बीच अंदरूनी कलह का इस चुनाव पर असर पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सैलजा दलित वोटो को बहुत ज्यादा ट्रांसफर कर सकती हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वह दलितों का एक प्रतीक बनकर उभरी है। दलितों में इस बात की भी नाराजगी हो सकती है कि दलितों के प्रतीक सैलजा को घर बिठा दिया गया, उन्हें और उनके प्रत्याशियों को भी चुनाव नहीं लड़ने दिया, नब्बे में से 72 टिकट हुड्डा ने बांटे। शायद दलितों की इस नाराजगी को भांपकर ही कांग्रेस ने अंतिम क्षण में अशोक तंवर को लाकर एक संकेत देने की कोशिश की, कि हम आपका ध्यान रखते हैं और आपके एक और दलित नेता हमारे साथ हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर भाजपा हरियाणा चुनाव हार जाती, तो आगे जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां विपक्ष की तरफ वोटों का रुझान होता और भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। लेकिन अब उस पर विराम लग गया है।

आज का इतिहास

1956 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ।
1963 जेम्स बॉन्ड की दूसरी फिल्म रूस से प्यार को लंदन में परदे पर दिखाया गया।
1964 1964 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह इन्टोक्यो में हुआ, जो पहली बार उपग्रह के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया गया।
1964 टोकियो में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया गया।
1967 आउटर स्पेस ट्रीटी, एक संधि है जो इनिन्टेशनल स्पेस लॉ का आधार बनती है, जो बल में प्रवेश करती है।
1970 फ़िजी को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली और इस दिन को इस देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया।
1973 संयुक्त राज्य के उपराष्ट्रपति स्पाइरो एग्न्यू ने कर चोरी के आरोप के बाद इस्तीफा दे दिया।
1978 डैनियल अराप मोई को केन्या के राष्ट्रपति चुना गया।
1981 जासूस इंस्पेक्टर एलेक्जेंड्रा ड्रेक के माता-पिता लंदन में एक कार विस्फोट में मारे गए।
1982 मैक्सिमिलियन कोल्बे , जिन्होंने ऑशविट्ज़ इनपोलैंड के नाजी एकाग्रता शिविर में एक अजनबी की मृत्यु के लिए स्वेच्छा से कैथोलिक चर्च द्वारा विहित किया था।
1982 मैक्सिमिलियन कोल्बे, जिन्होंने पोलैंड में औशविट्ज़ के नाजी एकाग्रता शिविर में खगोलविद के स्थान पर मरने के लिए स्वेच्छा से कैथोलिक चर्च द्वारा वसीयत की थी।
1986 सैन सल्वाडोर में 7.5 तीव्रता वाले भूकंप में 1,500 लोगों की मौत हुई।
2005 एंजेला मार्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनीं।
2006 नाइजीरिया के बेएलासा राज्य में एक नौसैनिक अड्डे और तेल की सुविधा, सुसज्जित हमलावरों द्वारा ले ली गई है। ऐसा माना जाता है कि वे 60 लोगों को बंधक बना रहे हैं।
2008 ऑक्सफैम के अनुसार, इथियोपिया में खाद्य सहायता की आवश्यकता 6.4 मिलियन तक बढ़ गई है, जो जून में लगभग दो मिलियन अधिक है।
2009 इंग्लैंड के मैनचेस्टर में इस्लाम विरोधी और नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनों के बीच संघर्ष के बाद लगभग 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
2011 बेल्जियम और फ्रांस ने बेल्जियम के सबसे बड़े बैंक डेक्सिया को तोड़ने और आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करने पर सहमति व्यक्त की है।

हरियाणा चुनाव परिणाम के दूरगामी असर होंगे

रशीद किदवई

कांग्रेस के सामने इस नतीजे से अनेक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हरियाणा में वह आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर सकी थी। यह बात भी उठेगी। साथ ही, कद्दावर कांग्रेस नेता शैलजा के साथ पार्टी के भीतर जो हुआ और उन्हें हाशिये पर रखने की कोशिश हुई, वह मसला भी अब उभरकर सामने आयेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों के बाद अब हरियाणा के परिणाम ने भी साफ कर दिया है कि जब भी कांग्रेस किसी राज्य में अपने क्षत्रप के भरोसे चुनाव लड़ती है, तो उसे हार का मुंह देखना पड़ता है।

भाजपा हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस नतीजे के राजनीतिक असर दूर तक होंगे। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो वे राजनीतिक रूप से सशक्त हुए हैं। केंद्र सरकार में उनके गठबंधन में शामिल दल राज्यों के चुनाव को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, उन्हें यह अहसास हो गया है कि मोदी में अभी बहुत दम-खम बाकी है और भाजपा अपने बूते पर चुनाव जीतने में सक्षम है। उसके विरोधी, खासकर कांग्रेस, आमने-सामने की लड़ाई में भाजपा के सामने कमजोर पड़ जाती है। एनडीए के घटक दलों को अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर दबाव बनाना पहले की अपेक्षा मुश्किल हो जायेगा। आगामी दिनों में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में शिंदे शिव सेना और अजीत पवार की एनसीपी के सामने भाजपा का कद बहुत बढ़ गया है। हरियाणा में भाजपा का कोई क्षत्रप भी नहीं था। यह चुनाव कांग्रेस मोदी सरकार की नीतियों- किसान, जवान, पहलवान- को मुद्दा बनाकर लड़ी थी। इन आलोचनाओं को मतदाताओं ने नकार दिया है। एक अहम पहलू दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान के खतरे में होने की जो बात कह रहे थे, वह मुद्दा भी कामयाब नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को उसका फायदा हुआ था, पर हरियाणा में उस मुद्दे पर अंकुश लग गया है। अब आगे अगर राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठायेंगे, तो संभव है कि पार्टी में ही उसका विरोध हो कि इन मसलों का असर नहीं हो रहा है।

कांग्रेस के सामने इस नतीजे से अनेक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हरियाणा में वह आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर सकी थी। यह बात भी उठेगी। साथ ही, कद्दावर कांग्रेस नेता शैलजा के साथ पार्टी के भीतर जो हुआ और उन्हें हाशिये पर रखने की कोशिश हुई, वह मसला भी अब उभरकर सामने आयेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों के बाद अब हरियाणा के परिणाम ने भी साफ कर दिया है कि जब भी कांग्रेस किसी राज्य में अपने क्षत्रप के भरोसे चुनाव लड़ती है, तो उसे हार का मुंह देखना पड़ता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के भरोसे पार्टी ने पूरा चुनाव छोड़ा था। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में पूरी कमान दे दी गयी थी। हुड्डा को लगभग 72 सीटों पर उम्मीदवार चुनने की छूट दी गयी थी। चुनावी रणनीति बनाने का काम भी उन्हीं के जिम्मे था। पर राज्य में सत्ता हासिल करने की तमन्ना पूरी नहीं हो सकी। सुनील कानूगोलू कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रबंधन का काम देखते हैं।

उन्हें प्रशांत किशोर की तरह चुनावी रणनीतिकार माना जाता है और उन्हें कर्नाटक में मंत्री पद के समकक्ष ओहदा भी दिया गया है। उनके नेतृत्व में हुए कांग्रेस के आंतरिक सर्वेक्षण के आधार पर जो दावे हुए, जो रणनीति बनायी गयी, वे सब नाकाम साबित हुए।

किसी राज्य या क्षेत्र में क्या राजनीतिक स्थिति है, उसे समझना कोई मुश्किल काम नहीं होता। जम्मू-कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस को पता था कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है। उसे लेकर पार्टी ने कोई बड़े दावे नहीं किये। फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर हरियाणा में ऐसा कैसे हुआ। राहुल गांधी का तो आत्मविश्वास इतना था कि वे चुनाव घोषित होने के बाद अमेरिका चले गये। कहा जा सकता है कि अत्यधिक आत्मविश्वास, क्षत्रप पर पूरा भरोसा और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं का टकराव कांग्रेस की हार के मुख्य कारण हैं। यह तथ्य है कि जाट समुदाय को लेकर दलितों में डर और आशंका का माहौल होता है, उसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गयी। कुमारी शैलजा 14 दिनों तक कोप भवन में रहीं। समय रहते उनको मनाने की कोशिश क्यों नहीं की गयी? वे राज्य में पार्टी की अध्यक्ष हैं और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें याद नहीं कि पिछली बार कब उनकी बातचीत हुड्डा से हुई थी। सुरजेवाला और हुड्डा की भी नहीं पटती। जब शीर्ष नेताओं के बीच ऐसे रिश्ते होंगे, तो फिर चुनाव कैसे जीता जा सकता है! अब कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन बनाने में मुश्किलें आयेंगी क्योंकि वे सीटों के बंटवारे पर आसानी से तैयार नहीं होंगे।

लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित होकर कांग्रेस अनेक सपने देखने लगी थी कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, फिर झारखंड, फिर बिहार और दिल्ली भी इंडिया गठबंधन की सरकारें बनेंगी। योगेंद्र यादव ने कह भी दिया था कि जीतों के इस सिलसिले के बाद मोदी जी के विदाई का समय आ जायेगा। हालांकि हरियाणा जीतना कोई अनहोनी बात भी नहीं लगती थी क्योंकि राज्य में दस साल से भाजपा सत्ता में है, चुनाव से कुछ समय पहले एक मुख्यमंत्री को दूसरे व्यक्ति को कमान दी गयी, कई मुद्दों पर जनता में भी नाराजगी थी, लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर कांग्रेस हकीकत को ठीक से नहीं समझ सकी। यह बड़ी चूक है और मुझे लगता है कि इससे उबरने में पार्टी को समय लगेगा। इस चुनाव ने फिर साबित किया है कि किसी भी पार्टी को अपनी मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए। भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में, खासकर घाटी में, वोट बांटने की रणनीति अपनायी थी, पर वह सफल नहीं रही क्योंकि इसके लिए वह दूसरों के भरोसे थी। हरियाणा में भी अन्य दलों ने अपनी भूमिका निभायी है, पर कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लेती और टिकट बंटवारा बेहतर होता, तो शायद आज नतीजे अलग होते।

भाजपा की यह जीत उसके लिए एक तरह से संजीवनी ही कही जायेगी। लोकसभा चुनाव में पार्टी की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पायी थीं। अगर भाजपा हरियाणा हार जाती, तो यही संदेश जाता कि हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस के उभार का दौर शुरू हो गया है और भाजपा अब एक तरह से सियासी ढलान पर है। जैसे हरियाणा में जाट समुदाय है, वैसे ही महाराष्ट्र में मराठा हैं। वहां भी बड़ी तादाद में दलित और पिछड़े समुदाय हैं, जिनका वोट है। इस चुनाव के बाद एक बार फिर अब कांग्रेस के समक्ष एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हो गयी है कि वे महाराष्ट्र में सहयोगी दलों और मतदाताओं के विभिन्न समूहों को लेकर कैसे एक ठोस एवं संतुलित रणनीति अपनायें। यही बात झारखंड एवं अन्य राज्यों के बारे में कही जा सकती है, जहां आगामी महीनों में विधानसभा के चुनाव संभावित हैं।

जम्मू-कश्मीर में नई शुरुआत का समय

शेखर अय्यर

दस वर्ष बाद जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब वहां जल्द नई सरकार का गठन होगा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है। भाजपा बेशक जम्मू-कश्मीर में सरकार नहीं बना पा रही है, लेकिन पिछले दिनों हुई तमाम आतंकी वारदात के बावजूद जम्मू-कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव करा कर सरकार ने एक संदेश तो दिया ही है, यहां के लोगों ने प्रचंड बहुमत का उपयोग कर भारतीय लोकतंत्र पर मुहर भी लगाई है। उल्लेखनीय है कि पहली बार यहां अनुसूचित जातियों के लिए सात और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौ सीटें आरक्षित की गईं। हालांकि, भाजपा को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों का उसे फायदा मिलेगा, लेकिन हैरत नहीं होनी चाहिए कि कश्मीर घाटी के लोग उसे स्वीकारने के मूड में नहीं दिखे। जम्मू हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन घाटी के लोगों ने हमेशा से भाजपा से इतर दलों को ही प्राथमिकता दी है। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को नकारने के पीछे के कारण उनके बयान और भाजपा के साथ पूर्व में किया गया गठबंधन है। फिलहाल की स्थितियों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तक खुद को पहुंचाने के लिए घाटी के लोगों के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिताने का ही विकल्प मौजूद था। यही वजह थी कि उन्होंने छोटे निर्दलीय दलों को नकार?कर सबसे बड़े दलों को वोट किए। 2014 में हुए जम्मू-कश्मीर के चुनाव के नतीजों?को देखें, तो पीडीपी ने 28, भाजपा ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि भाजपा को सबसे ज्यादा 22.98 फीसदी वोट मिले थे, जबकि पहले नंबर पर रही पीडीपी को 22.67 फीसदी मत मिले थे। इस बार के परिणामों में भी यही हुआ है। भाजपा की चार सीटें बढ़कर 29 हो गई हैं, जबकि उसका वोट प्रतिशत 25.64 फीसदी रहा है। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन उसका वोट प्रतिशत 23.43 प्रतिशत ही है। भाजपा को ये सीटें जम्मू क्षेत्र से ही मिली हैं, पिछली बार भी उसे जम्मू क्षेत्र से ही सीटें मिली थीं। पिछले चुनावी नतीजो पर नजर डालें, तो जम्मू-कश्मीर में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। 2009 में वह 11 सीटें ही जीती थी, उसका वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है, लेकिन भाजपा को घाटी में कोई आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही। गौरतलब है कि संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित कर जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया था। ऐसे में चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास होंगी। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव का परिणाम यही दर्शाता है कि वहां की जनता अब एक स्थिर सरकार चाहती है, जो उनके विकास के लिए काम करे। ऐसे वक्त में, उमर अब्दुल्ला प्रमुख रूप से उभरे हैं, जो 2009 से 2015 तक छह वर्ष राज्य के मुख्यमंत्री रहे। अब संभावना है कि वह केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भले ही उनकी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को भावनात्मक मुद्दा बनाया हो, लेकिन हर कोई जानता है कि 370 की वापसी अब संभव नहीं। ऐसे में जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए जरूरी है कि उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार से टकराव करने के बजाय सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। यदि वह कांग्रेस की योजना के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा से टकराव जारी रखेंगे, तो यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के हित में भी नहीं होगा।

भाजपा को दमदार अध्यक्ष की तलाश

प्रभु चावला

जेपी नड्डा का भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जून में समाप्त हो गया, लेकिन वे पद पर बने हुए हैं क्योंकि नेतृत्व नये नाम पर सहमत नहीं हो पा रहा है। नड्डा न सिर्फ अंतरिम पार्टी प्रमुख हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब पार्टी को लोगों की नजर में अनिर्णय की कमजोरी को दूर करने के लिए इस मुद्दे को जल्दी हल करना होगा। असंख्य सांसदों और मुख्यमंत्रियों वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी प्रतिभा के अकाल से जूझ रही है। सत्ता में बिताये गये सुखद दिनों ने सफल प्रशासकों का एक समूह तैयार कर दिया है। जब भाजपा विपक्ष में थी, तो पार्टी प्रमुख के रूप में उनकी जगह भरने के लिए एक अटल या एक आडवाणी के स्थान पर चार विकल्प होते थे। अब, जब इसके 12वें अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया चल रही है, तो कई नामों पर स्याही अभी सूखी नहीं है।

शिवराज सिंह चौहान ने 1972 में 1× साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक के रूप में सामाजिक सेवा शुरू की थी। अब वे 65 वर्ष के हैं और अध्यक्ष पद की दौड़ में अग्रणी प्रतीत होते हैं। उनके पक्ष में उम्र, जाति, विश्वसनीयता, अनुभव और स्वीकार्यता हैं। वे तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं, संघ के प्रिय हैं और विपक्ष उन्हें सबसे कम नापसंद करता है। वे लोकप्रिय हैं तथा उनकी अभिनव कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं ने भाजपा को रा'य में लगभग अजेय बना दिया। हिंदुत्व उनके शासन का मूल सिद्धांत रहा है। वाजपेयी और आडवाणी दोनों ने उन्हें भविष्य के नेता के रूप में पहचाना था और 2005 में उन्हें मुख्यमंत्री और भाजपा संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया था। वे किसान-समर्थक समृद्धि उपायों के प्रस्तोता हैं और उन्हें भारी ग्रामीण समर्थन प्राप्त है। पर उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व उनके लिए अवरोध हो सकता है। देवेंद्र फड़नवीस ×5 वर्षों से संघ परिवार से जुड़े हैं। नागपुर के इस 54 वर्षीय नेता ने विद्यार्थी परिषद से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। साल 2014 में सत्ता में

आने के बाद प्रतिभा को पहचानने वाले मोदी और शाह ने ब्राह्मण जाति के फड़नवीस को, जो उस समय 44 वर्ष के थे, भारत के सबसे अमीर रा'य महाराष्ट्र का दूसरा सबसे युवा मुख्यमंत्री बनाया। उनकी खातिर नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे जैसे वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की गयी। किसी भी स्थानीय गुट से फड़नवीस की दूरी और सर्वोँच नेताओं से निकटता ने उन्हें दौड़ में आगे कर दिया है। पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा सांगठनिक कार्य नहीं संभाला है। मोदी-शाह के प्रति उनकी वफादारी उन्हें शीर्ष पर पहुंचाने के लिए शायद पर्याप्त न हो।

रजवाड़ा पृष्ठभूमि से आने वालीं 71 वर्षीय वसुंधरा राजे अभी पीछे हैं, पर निश्चित ही मैदान से बाहर नहीं हैं। तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए उनके दावे को आलाकमान ने खारिज कर दिया था। वे अभी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से एक हैं। यद्यपि संघ से उनका जुड़ाव कमजोर हो गया है, लेकिन उनकी दिवंगत मां विजया राजे की विरासत की बदौलत संघ नेतृत्व उनके प्रति सकारात्मक है। वसुंधरा केंद्र, रा'य और पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। वे राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। यदि भाजपा अपनी पहली महिला अध्यक्ष की तलाश में है, तो राजे की वरिष्ठता, अनुभव और गंभीरता माकूल बैठती है। उनकी बाधा यह है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ाव वाली कोई राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं संभाली है। इसके अलावा, उन्होंने मोदी-शाह की जोड़ी से दूरी बना रखी है। विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से आने वाले 55 वर्षीय उड़िया नेता धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा और दिल्ली में संघ और भाजपा की गतिविधियों में प्रभावी रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व उन्हें एक संभावित राष्ट्रीय नेता और वैचारिक रूप से भरोसेमंद के रूप में देखता है। वे राष्ट्रीय महासचिव हैं और उन्होंने कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में चुनावी जिम्मेदारी संभाली है। प्रधान आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक रहने वाले पेट्रोलियम मंत्री हैं। उनका कौशल शासन के लिए अधिक अनुकूल है, हालांकि विरोधियों का आरोप है कि उनके पास राष्ट्रीय कद और अखिल भारतीय स्वीकार्यता का अभाव है।

राजस्थान में जन्मे 55 वर्षीय वकील भूपेंद्र यादव ने अपना राजनीतिक करियर संघ-नियंत्रित वकीलों के संगठन से शुरू किया। अटल-आडवाणी युग के दौरान वे एक संभावित राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे। उन्हें 2010 में नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय सचिव के रूप में चुना था। तब से, गैर-विवादित यादव पर शीर्ष ने भरोसा किया और उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण पद मिले। साल 2014 में शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद वे उनकी टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य बने। महासचिव के रूप में उन्होंने राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रबंधन किया। उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने में भी सक्रिय भूमिका निभायी थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में उनका महत्व स्पष्ट है, जो मोदी के विकसित भारत के एजेंडे के लिए एक अति संवेदनशील मंत्रालय है। पर संघ के एक वर्ग का मानना है कि वे अभी बहुत कनिष्ठ हैं। भाजपा में महासचिव बनने से पहले 55 वर्षीय सुनील बंसल संघ प्रचारक थे। विद्यार्थी परिषद और संघ के अनुभव ने उन्हें एक उत्कृष्ट टीम लीडर बना दिया है। जब शाह ने 2014 में भाजपा के चुनाव अभियान की कमान संभाली, तो उन्होंने बंसल को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया, जहां पार्टी को भारी जीत हासिल हुई। इस बार उन्हें ओडिशा की कमान सौंपी गयी, जहां भाजपा पहली बार सत्ता में आयी। पर नेतृत्व का एक वर्ग सोचता है कि बंसल को अधिक अनुभव की आवश्यकता है।

जम्मू-कश्मीर का संदेश और आगे की राह

पूनम आई. कौशिश

वस्तुत: जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव नए तथा अनेक मामलों में अलग थे। पहली बार 5 अगस्त, 2019 को यह एक संघ राज्य बना और इसका विशेष दर्जा समाप्त किया गया। पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का विभाजन किया गया। चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन से जम्मू क्षेत्र की सीटें बढ़कर 43 हुईं और कश्मीर क्षेत्र की 1 सीट बढ़कर 47 हुईं। 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गईं और 5 सीटों पर उपराज्यपाल द्वारा सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा।

यह भारत के चुनावी सत्यनिष्ठा का प्रमाण है कि राज्य में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं क्योंकि वहां पर 10 वर्षों के बाद चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में मतदाताओं, उम्मीदवारों और पार्टियों ने व्यापक रूप से भाग लिया। मतदान भी 62 प्रतिशत से अधिक हुआ। महिलाओं और युवाओं में मतदान के लिए उत्साह था। मतदान में कोई हिंसा या जोर-जबरदस्ती नहीं हुई। वस्तुत: संदेश स्पष्ट है कि ये चुनाव जनकेन्द्रित और जनता द्वारा प्रेरित थे, जिसमें जनता का बोलबाला रहा और उसने अपनी आवाज उठाई तथा अपने भाग्य को भी निर्देशित किया।

मतदाताओं ने बताया कि उन्होंने बहिष्कार की बजाय मतदान को प्राथमिकता दी और इस तरह उन्होंने देश-विरोधी ताकतों को पराजित किया और लोकतंत्र की जीत हुई। यह एक दूरगामी बदलाव था और इसने इस वास्तविकता को बदला कि अतिवादी संगठन जमात-ए-इस्लामी, जिसने दशकों तक चुनावों का बहिष्कार किया और जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसने भी चुनावों में भाग लिया। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के आरोपी बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद द्वारा लोकसभा का चुनाव जीतने से एक नया मोड़ आया। उनकी आवामी इत्तेहाद पार्टी, जो फारूक अब्दुल्ला की नैशनल कांफ्रैंस की विचारधारा के विपरीत है, उसने लोगों की इच्छा को भांपा और इन सबकी उपस्थिति ने चुनावी जंग में स्थापित परिवारवादी पार्टियों नैकां और पी.डी.पी. तथा भाजपा और कांग्रेस के लिए एक नया अनुभव दिया। यह इस क्षेत्र के लिए शुभ संकेत है जिसने दशकों तक आतंकवाद को झेला है। राजनीतिक वर्ग के लिए चुनौती यह है कि वह चुनावी लोकतंत्र में जनता के अटूट विश्वास को बनाए रखे और इस बात का प्रयास करे कि वे सुरक्षा चुनौतियां, सामाजिक चिंताओं, आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने और राजनीतिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम है और साथ ही सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले, पुंछ और राजौरी आदि क्षेत्रों में हिरासत में मौतों पर जनता की चिंताओं को दूर करे।

नि:संदेह आर्थिक और शासन के मोर्चों और सेवाओं में सुधार हुआ है। एक हजार से अधिक जनउपयोगिता सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। 6 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की बड़ी परियोजनाएं लगभग पूरी होने वाली हैं। तथापि एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि आर्थिक और प्रशासनिक उपायों के फलीभूत होने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। साथ ही हमें शीघ्र ही आतंकवाद रोधी कार्रवाइयों को तेज करना होगा क्योंकि युवाओं में कट्टरपन बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी दूर करना एक मुख्य चुनौती है। वस्तुत: केन्द्र सरकार को घाटी में होने वाली घटनाओं को सहानुभूतिपूर्वक देखना होगा क्योंकि इससे हमारे मनुवादी समाज का ध्रुवीकरण हो सकता है और राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो सकता है। उसे अनेक विकास परियाजनाएं चलानी होंगी। हालांकि घाटी में पर्यटन बढ़ रहा है, तथापि सरकार को स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना होगा और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि संपूर्ण देश से व्यापार और निवेश के लिए लोगों का आना-जाना वहां बढ़े।

जम्मू-कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक संकेतक उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों से बहुत अच्छे हैं और यहां पर विकास में तेजी लाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप तथा धन, जन बल और बाहुबल के अलावा कश्मीर को एक भावनात्मक पैकेज की आवश्यकता है। आशा की जाती है कि नई सरकार पाकिस्तान द्वारा भ्रमित किए गए कश्मीरियों विशेषकर युवाओं को अपने दुख, हताशा, गुस्से को व्यक्त करने का अवसर देगी। साथ ही उनके साथ सम्मान का व्यवहार करना होगा, उनकी गरिमा बहाल करनी होगी और उनके अपमान के घावों पर मरहम लगाना होगा। कुल मिलाकर सरकार अलग-थलग पड़े युवाओं को मुख्य धारा में लाए, रोजगार के अवसर सृजित करे और बिना किसी समझौते के आतंकवाद का कठोरता से सामना करे। आतंकवादी घाटी और जम्मू के बीच जीवन रेखा के रूप में राजमार्गों को निशाना बना सकते हैं, इसलिए स्थानीय पुलिस के साथ सी.आर.पी.एफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। अब देखना यह है कि क्या जम्मू-कश्मीर की जनता विकास के वायदों से संतुष्ट होती है, क्योंकि कश्मीरियों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा। वे भारतीय सुरक्षा बलों की ज्यादतियों को अस्वीकार करते रहे हैं, क्योंकि इससे जनता का दिल नहीं जीता जा सकता है।

समय आ गया है कि नए निर्वाचित प्रतिनिधि कश्मीरियों को देश की मुख्यधारा में लाएं। राज्य सरकार के पदों तथा शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करें तथा उनके साथ विषमता को दूर करें। सरकार को स्थानीय लोगों के साथ संवाद करना चाहिए ताकि एक नए जम्मू-कश्मीर का निर्माण हो सके। हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि एक सुदृढ़ और स्थिर जम्मू-कश्मीर का निर्माण हो जबकि सुदृढ़ तथा स्थिर जम्मू-कश्मीर भारत के बहुलवादी समाज तथा इसके फलते-फूलते लोकतंत्र की एक बड़ी उपलब्धि होगी। राज्य के नेताओं को भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और कश्मीरी लोगों को सच्चे रूप से यह अहसास कराने कि भारत उनका देश है, इस दिशा में भरसक प्रयास करना होगा। कुल मिलाकर यह एक ऐसा चुनाव है जिसकी गूंज इतिहास के पन्नों में गूंजेगी। समय आ गया है कि सरकार बुनियादी बातों पर ध्यान दे, अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाए और विविध धर्मों वाले राष्ट्र में सहिष्णुता तथा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करे व सही इरादों और उचित आशा के सिद्धान्त के साथ जनता के लिए कार्य करे। क्या नया नेतृत्व वास्तव में जम्मू-कश्मीर में चेरी खिला और कश्मीर के सपने को एक बड़ी वास्तविकता बना सकता है?

हरियाणा में कांग्रेस के हाथ फिर लगी हताशा

विनोद पाठक

एक्जिट पोल एकबार फिर फेल साबित हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी भविष्यवाणियों को झूठलाते हुए भाजपा जीत की हैट्रिक लगाती दिख रही है। सुबह शुरुआती रुझानों में भले भाजपा कांग्रेस से बहुत पीछे थी, लेकिन सुबह साढ़े नौ बजे के बाद उसने ऐसा कमबैक किया, जिसने सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। हरियाणा के रुझान यदि नतीजों में बदलते हैं तो भाजपा को एक बूस्टर डोज यहां से मिलने वाली है। एक नए उत्साह का संचार पार्टी में होने वाला है। निश्चित ही इसका प्रभाव आगामी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। खत्री पंजाबी के बजाय ओबीसी पर दांव लगाया था। तब यह माना जा रहा था कि सैनी को बलि का बकरा बना दिया गया है, लेकिन अब रुझानों से साफ हो गया है कि भाजपा का ओबीसी कार्ड सही साबित हुआ। भाजपा को बहुत बड़ा फायदा अहीरवाल क्षेत्र, जिसमें गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल जिले आते हैं, में हो रहा है। भाजपा वर्ष 2014 से अहीरवाल क्षेत्र में मजबूत रही है। इसका एक बड़ा कारण केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी हैं। राव इंद्रजीत सिंह जब तक कांग्रेस में थे, तब तक अहीरवाल क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत थी, वो जब से भाजपा में आए हैं, इस क्षेत्र में भाजपा मजबूत हो गई है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में जाट क्षेत्र, जिसमें रोहतक, झज्जर और सोनीपत आते हैं, से काफी अच्छा समर्थन मिला था। इन जिलों में जाट मतदाताओं की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह प्रभाव वाला क्षेत्र है। हुड्डा के कारण कांग्रेस पिछली चुनाव में 31 सीटें जीतने में सफल रही थी, लेकिन केवल जाट वोटों के सहारे कांग्रेस की नैया पार होती नहीं नजर आ रही। यदि हरियाणा में जातीय समीकरणों को देखें 22 प्रतिशत जाट, 20 प्रतिशत दलित, 30 प्रतिशत ओबीसी, 16.5 प्रतिशत जनरल, 8 प्रतिशत पंजाबी और 3.5 प्रतिशत मुस्लिम वोट हैं। जब कांग्रेस के पक्ष में जाट मतदाता लामबंद हुए तो बाकी जातियों ने गुपचुप भाजपा के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के पास जाट वोटों के अलावा दलित और मुस्लिम वोट भी हैं, लेकिन चुनाव के रुझान बता रहे हैं कि भाजपा ने कांग्रेस के दलित वोट में सेंध लगा दी है। ऐसे में कुमारी शैलजा का महत्व कांग्रेस में बढ़ाने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अब केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भरोसे हरियाणा को नहीं जीत सकती, यह बात उसे समझ में आ रही होगी। भाजपा की सोशल वेलफेयर स्कीम्स और महिलाओं को लेकर चलाई जा रही योजनाओं ने काफी काम किया है। महिलाओं का ऐसा विषय है, जिसे किसी भी सर्वे या एक्जिट पोल ने उस तरीके से नहीं उठाया, जैसा उठाया जाना चाहिए था। यह माना जा रहा है कि महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में बिना शोर मचाए वोट किया है, जैसा मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। एक और मुद्दा जो राहुल गांधी ने अपनी हर सभा में उठाया, वो अग्निवीर स्कीम का है। हरियाणा में इस मुद्दे को इसलिए भी बड़ा बताया जा रहा था, क्योंकि हरियाणा से सेना में बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। अब अग्निवीर का मुद्दा थोड़ा धीमा होगा, यह दिख रहा है। किसान या पहलवान के मुद्दे भी कांग्रेस के बहुत काम नहीं आए हैं। वैसे हरियाणा में इस चुनाव में राहुल गांधी प्रचार से थोड़ा दूर रहे। वो अंतिम तीन दिन ही प्रचार में उतरे। बहुत कम चुनावी सभाएं कीं। उनके मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अधिक सभाएं कीं। ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत हरियाणा में लगा दी थी। यदि दूसरी पार्टियों की बात करें तो इनेलो, आम आदमी पार्टी और बसपा ने कहीं न कहीं कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाई है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से चुनाव पूर्व समझौता चाहती थी, जिसे कांग्रेस ने नकार दिया था। आम आदमी पार्टी को 1.65 प्रतिशत के आसपास वोट मिल रहे हैं, जबकि इनेलो 4.52 प्रतिशत वोट ले रही है और बसपा ने भी 1.63 प्रतिशत के आसपास वोट लिया है। यदि इंडी गठबंधन एक होता तो कांग्रेस को कुछ फायदा जरूर होता। रुझानों से साफ दिख रहा है कि भाजपा हरियाणा में फिर सरकार बना रही है। नायब सिंह सैनी को पुरस्कार मिलता दिख रहा है।

स्टार्टअप शुरू करने में थोड़ी इनवेस्टमेंट की जरूरत होती है जो कई लोगों के लिए मुश्किल काम होता है। ऐसे में अगर कोई ऐसा बिजनेस हो जिसे कम लागत में शुरू किया जा सके तो आप जरूर करना चाहेंगे। यहां हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक लाख रुपए से कम लागत में भी शुरू किए जा सकते हैं।

कम लागत से शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस होगी लाखों में इनकम

आजकल स्टार्टअप का जमाना है।हर कोई नौकरी की बजाए अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहता है। स्टार्टअप शुरू करने में थोड़ी इनवेस्टमेंट की जरूरत होती है जो कई लोगों के लिए मुश्किल काम होता है।ऐसे में अगर कोई ऐसा बिजनेस हो जिसे कम लागत में शुरू किया जा सके तो आप जरूर करना चाहेंगे।यहां हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक लाख रुपए से कम लागत में भी शुरू किए जा सकते हैं। हम यहां जिन कामों के बारे में बताने जा रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें महज 50,000 रुपए की लागत से शुरू किया जा सकता है।इनवेस्टमेंट के हिसाब से इन कामों को बढ़ाया भी जा सकता है।

पुरानी कारों की डीलरशिप

भारत में कारों का बिजनेस खूब बढ़ रहा है ऐसे में नई कारों की डीलरशिप के साथ-साथ सेकंड हैंड कारों का बाजार भी डिमांड में है। आप पुरानी कारों की डीलरशिप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। डीलरशिप के अलावा इसमें आप कमिशन भी कुछ कमा सकते हैं। बशर्ते आप को क्लाइंट को ढूंढ़ना होगा और उनको डील करानी होगी।

इवेंट फोटोग्राफर

फोटोग्राफर बनने के लिए बस आपको एक कैमरे की जरूरत होती है जो कि 50 हजार से कम कीमत में कहीं से भी ले सकते हैं। इस काम के लिए आपके भीतर जुनून और किसी भी चीज की खूबसूरती देखने और उसे कैमरे में कैद करने का हुनर होना जरूरी है। लोगों के फैमिली फंक्शन, शादी, बर्थडे पार्टी, सोसाइटी के कार्यक्रमों आदि में फोटोग्राफर की डिमांड होती है।किसी भी इवेंट को यादगार बनाने के लिए फोटोग्राफी जरुरत बन गईहै।ऐसे में आप फोटोग्राफी के जरिए अच्छा पैसा कमा सकते हैं।

ड्राइविंग स्कूल

ड्राइविंग स्कूल शुरू करना एक बेहतरीन आयडिया है और देश में गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये बिजनेस कभी भी घाटे में नहीं रहने वाला। शहरों में तो आजकल एक भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ड्राइविंग नहीं सीखना चाहता हो।इसके लिए आपको सिर्फ एक गाड़ी की जरुरत पड़ती है जो कि आप सेकेण्ड हैंड भी खरीद सकते हैं।एक अनुमान के मुताबिक कुछ ड्राइविंग स्कूल चलाने वाले लोग एक दिन में 8 से 10 हजार रुपए तक कम लेते हैं। इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव होना जरूरी है या फिर आप किसी दूसरे आदमी से भी क्लासेज दिलवा सकते हैं।

आइस क्रीम पार्लर

आइस क्रीम पार्लर भी एक बढ़िया निवेश है। सर्दियों के मौसम को छोड़ दें तो ये हमेशा मांग में रहता है।इसके लिए आपको बस एक फ्रीजर खरीदना होता है या फिर आप आइसक्रीम कंपनियों की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं।इनमें क्वालिटी वडीलाल जैसी बड़ी आइसक्रीम कंपनियां शामिल हैं और ये कंपनियां आइसक्रीम बिक्री का 10-20 फीसदी तक कमीशन के रुप में देती हैं।

मोबाइल गैरेज

शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी कारों की संख्या में तेजी से बढ़ात्तरी हो रही है। आम वाहनों की तरह कार में भी खराबी आना आम समस्या है।ऐसे में कार के मालिक को जरूरत होती कि कार जहां खड़ी है वहीं पर कोई मैकेनिक आकर कार रिपेयर कर जाए। ऐसे में यदि आप कार- ऑटो रिपेरिंग का थोड़ा बहुत अनुभव रखते हैं तो लोगों को मोबाइल गैरेज की सर्विस दे सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी है एक सेकंड हैंड बाइक और एक टूल बॉक्स जोकि दोनों में 50 हजार तक में आ जाएंगे।अपने साथ आप एक हेल्पर या मैकेनिक रखें तो बेहतर होगा।मोबाइल गैरेज के जरिए आप 2 से 5 हजार रुपए तक रोज कमा सकते हैं।

नौकरी चाहिए तो ऐसे बनाएं सोशल मीडिया प्रोफाइल

आजकल नौकरी पाने के लिए सिर्फ आपका ज्ञान और स्किल्स ही काफी नहीं है, सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट भी इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। आपने अपने फेसबुक पर क्या लिखा या ट्विटर पर कैसे ट्वीट किए या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपके बारे में क्या कहती है। आप सोशल मीडिया पर कैसे लोगों के संपर्क में हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अब कंपनियां ये सब भी नौकरी देने से पहले देख रही हैं। आज सोशल मीडिया के जरिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नजरिये के बारे में पता लगाना बहुत आसान हो गया है। यही वजह है कि मल्टीनेशनल और स्टार्टअप कंपनियां नौकरी पर रखने से पहले आवेदक के प्रोफाइल को परखती हैं। इससे उन्हें अंदाजा लग जाता है कि आवेदक उनकी कंपनी में फिट बैठता है या नहीं।

सोशल मीडिया पर सकारात्मक छवि होना जरूरी

इन सोशल मीडिया प्रोफाइल से कंपनियों को आवेदकों की रूचि, उसकी प्राथमिकताएं और विश्वसनीयता के बारे में पता चलता है, जिस आधार पर उनके लिए आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करना आसान होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर नौकरी मिले, तो ज्ञान के साथ-साथ सोशल मीडिया पर आपकी सकारात्मक छवि भी होनी चाहिए। करीब 30 फीसदी कंपनियां आवेदकों की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर यह देखती हैं कि अन्य लोग आवेदकों के बारे में क्या राय रखते हैं। सोशल मीडिया पर किए गए एक सर्वे में शामिल 60 फीसदी नियोक्ताओं ने उम्मीदवारों की ऑनलाइन मौजूदगी को परखने के बाद उन्हें खारिज कर दिया। इसका बड़ा कारण था उम्मीदवार के ऑनलाइन प्रोफाइल और रेज्यूमे में दी गई शैक्षिक योग्यता में अंतर।आवेदन के खारिज होने का बड़ा कारण था, पिछली कंपनी या अपने स्कूल-कॉलेज को बुरा बताने वाले पोस्ट डालना।इसके अलावा यह ध्यान रखें कि आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं, उसके बारे में कहीं भी बुरा न कह रहे हों।

सोच-समझकर सोशल मीडिया पर करें पोस्ट

वैसे तो सोशल मीडिया साइटों पर आम तौर पर लोग अपनी फोटो और अपने अनुभव शेयर करते है। लेकिन, सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो कभी शेयर ना करें जिसके कारण आपकी नकारात्मक छवि प्रस्तुत हों। आप सोशल साइट पर आपकी हॉबी या पसंदीदा चीजों से जुड़ी फोटो शेयर कर सकते हैं।इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान देते रहें कि कोई व्यक्ति किसी अश्लील तस्वीर या पोस्ट से आपको टैग तो नहीं कर रहा।इससे आपकी संगत और माहौल का अंदाजा लगाया जाएगा।

सोशल साइटों पर प्रोफेशनल दिखे

फेसबुक और लिंक्डइन पर आमतौर व्यक्ति की पहचान उसका फोटो देखकर ही की जाती हैं तो आप इसमें वही फोटो डाले जिसमें आप फार्मल लुक में हो।आपकी फुल शॉट तस्वीर से अच्छा है हेड शॉट वाली तस्वीर डालें, वो भी मुस्कराते हुए।आप प्रोफेशनली कैसे दिख रहे हैं, यह पता करने के लिए आप फोटोफीलर नाम की एक साइट पर अपनी फोटो अपलोड करें। इससे फोटो में आप आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में नजर आ रहे हैं या नहीं, यह पता लग जाएगा।

इंटरनेट पर आप किस तरह से हो रहे प्रस्तुत नौकरी के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया के दौरान या उससे पहले एक बार आप अपने नाम को गूगल पर सर्च करके देखे कि गूगल आपके नाम के बारें में क्या दिखाता है। नियोक्ता की नजर से आपकी अपने बारे में क्या राय बन रही है और संबंधित नौकरी के लिए आप खुद को हायर करेंगे या नहीं, इन सवालों का जवाब ढूंढें। जवाब 'न' में हो तो कारणों की सूची बनाएं। हो सकता है आपके पोस्ट गलत विचारधारा को प्रकट कर रहे हों या आपके दोस्त आपकी वॉल पर अनुचित तस्वीरें या अनुचित कमेंट डाल रहे हों। इसके लिए अपनी सेटिंग बदलें और दोस्तों से कहें कि वे ऐसी पोस्ट न डालें। नियोक्ता को आपकी प्रोफाइल कैसी दिख रही है, इसके लिए अपने फेसबुक पेज के ऊ पर दाएं कोने पर जाएं और प्रिव्यू माई प्रोफाइल पर जाकर देखें। आप चाहें तो अपने मुताबिक सेटिंग को एडिट भी कर सकते हैं।वैसे तो अधिकतर नियोक्ता उम्मीदवार को परखने के लिए उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाते हैं, पर कई बार क्षेत्र के हिसाब से भी दूसरी साइट पर आपकी मौजूदगी को भी परखते हैं।जैसे, अगर कोई डिजाइनर है तो उसकी पिनट्रेस्ट या टम्बलर प्रोफाइल को परखा जाता है, अगर कोई व्यक्ति मॉडल है तो उसके इंस्टाग्राम को परखा जाता है, वहीं निजी पृष्ठभूमि को जानने के लिए कंपनी फेसबुक प्रोफाइल को देखना पसंद करती है।

ऐसा होना चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल

लिंक्डइन अपने करियर क्षेत्र और पेशे से जुड़े पेशेवर लोगों से नेटवर्क बनाने का अच्छा जरिया है।अपने करियर क्षेत्र से संबंधित ग्रुप जॉइन करें। लिंक्डइन के मानदंडों के हिसाब से चलें।यदि आप चाहते हैं कि नियोक्ता, बॉस, या सहकर्मी आपके निजी ब्लॉग या पोस्ट को न देख पाएं तो इसके लिए सेटिंग पर जा कर लिंक्डइन प्रोफाइल में 'फीड' के सिंक ऑप्शन को अनचेक कर दें।लिंक्डइन पर डाले गए रेज्यूमे को बहुत से लोग देखते हैं। इसलिए जो सच है, वही लिखें।हाल की फोटो डालें।फॉर्मल ड्रेस में हेड शॉट डालें। अपने लिंक्डइन यूआरएल को छोटा रखें, जिससे गूगल पर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को ढूंढ़ना आसान हो। इसके लिए आप लॉगिन करें, अकाउंट और सेटिंग्स पर जाकर पब्लिक प्रोफाइल पर क्लिक करें और पेज पर यूआरएल एडिट करने का विकल्प चुने।

यदि आप फेसबुक प्रोफाइल को पेशेवर नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने प्रोफाइल में जरूरी बदलाव करने के लिए तैयार रहें। इसका मतलब है आपको कुछ कमेंट के साथ-साथ तस्वीरें हटानी होंगी, जो आपकी पेशेवर जिंदगी के लिहाज से ठीक न हों। अगर आपको पार्टी करना पसंद है और नहीं चाहते कि भावी बॉस आपकी पर्सनल प्रोफाइल देखें तो सारी प्राइवेसी सेटिंग में 'फ्रेंड्स ओनली' का ऑप्शन चुनें और कौन आपके प्रोफाइल को देखेगा, इसके प्रति सेलेक्टिव रहें। फेसबुक पर प्राइवेसी सेटिंग बदलें, ताकि यह तय हो सके कि आपके पेज को कौन देखेगा।इससे नियोक्ता भी आपसे एड हुए बिना आपकी प्रोफाइल को नहीं देख पाएंगे।इसके अलावा सेटिंग में बदलाव करें, ताकि लोग आपकी फेसबुक वॉल पर कोई अनुचित पोस्ट न डाल सकें।अगर आपने कहीं काम किया है और उस संस्था से जुड़े लोग आपकी फ्रेंडलिस्ट में हैं तो कस्टम सेटिंग का विकल्प चुन कर उन्हें अपनी निजी पोस्ट देखने से रोक सकते हैं।

ऐसा होना चाहिए ट्विटर अकाउंट

मार्केटिंग के क्षेत्र में उम्मीदवार के ट्विटर अकाउंट को देखने का चलन है।इससे पता चल जाता है कि उम्मीदवार का नेटवर्क कैसा है।ट्विटर प्रोफाइल को पब्लिक नहीं, प्रोफेशनल बनाएं। अपने करियर क्षेत्र से जुड़े ट्वीट डालें और फॉलो करें। अगर किसी कंपनी में सीनियर पोस्ट के लिए जा रहे हों तो 60 फीसदी ट्वीट आपकी इंडस्ट्री से जुड़े होने चाहिए।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

हरियाणा में जीत के बाद पीएम मोदी से मिले नायब सिंह सैनी

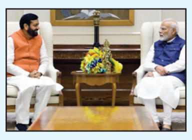

नईदिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में प्रचंड जीत के एक दिन बाद, राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनके नेतृत्व के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हरियाणा में भाजपा ने जीत की हैट्रिक बनाई है। पीएम आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सैनी ने कहा, इस बड़ी जीत का श्रेय पीएम मोदी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 साल में ऐसी नीतियां और योजनाएं बनाईं, जिनसे गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को फायदा हुआ है। सीएम ने कहा, यह जीत पीएम की नीतियों और पीएम मोदी के प्रति लोगों के प्यार और स्नेह का परिणाम है। इसके साथ ही सैनी ने कहा कि कांग्रेस का डीएनए ऐसा है कि उन्होंने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया। उन्होंने हमेशा उनका अनादर किया है।

सीएम पद संभालने से पहले ही उमर अब्दुल्ला ने दिखाए तेवर

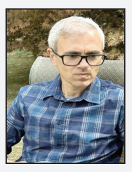

श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा से कहा कि वह भाजपा के सदस्यों को नामित न करें क्योंकि यह निर्वाचित सरकार और के बीच घर्षण में योगदान दे सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नई विधानसभा के लिए ऐसा कोई नामांकन किया जाता है तो नई सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और इससे जम्मू-कश्मीर और केंद्र सरकार के बीच संबंध तनावपूर्ण हो जाएंगे। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर दिल्ली के साथ विवादास्पद संबंध नहीं रख सकता, क्योंकि उसे क्षेत्र में जटिल मुद्दों को हल करने के लिए केंद्र की मदद की जरूरत है। बडगाम और गांदरबल के नए विधायक ने कहा कि लड़ाई होगी क्योंकि फिर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और इसके खिलाफ अपील करनी होगी। केंद्र के साथ हमारे संबंधों में पहले दिन से ही तनाव रहेगा, एक ऐसा संबंध जिसे हम बनाना चाहते हैं।

हरियाणा में कांग्रेस के पिछड़ने पर संजय राउत का बड़ा आरोप

मुंबई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद महाराष्ट्र में उसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) ने अकेले चुनाव लड़ने के कांग्रेस के फैसले पर असंतोष जताया है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने हालिया चुनावी नतीजों पर अपने विचार साझा किए और कांग्रेस की हार से सीखे जा सकने वाले सबक पर जोर दिया। राउत ने जोर देकर कहा कि हरियाणा के नतीजों का आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने राजनीतिक गुटों के बीच एकता और विनम्रता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि किसी को भी खुद को किसी और का बड़ा भाई नहीं समझना चाहिए। राउत ने हरियाणा में भारतीय गठबंधन की विफलता को भी संबोधित किया और सुझाव दिया कि संयुक्त मोर्चा चुनाव परिणाम बदल सकता था। उन्होंने यह विश्वास करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की कि वह अकेले जीत हासिल कर सकती है।

आप ने फिर किया साफ, दिल्ली में अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की संभावनाओं को खारिज करते हुए मंगलवार को दिल्ली में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद पार्टी के फैसले की पुष्टि की। हरियाणा में भाजपा विजयी हुई, जबकि उनकी पार्टी अपना खाता खोलने में विफल रही। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हम दिल्ली (विधानसभा) चुनाव अकेले लड़ेंगे। इसके साथ ही आप प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ अति आत्मविश्वास वाली कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकारी भाजपा है। हमने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में जो किया है उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। मंगलवार के चुनाव नतीजों ने हरियाणा में आप के लिए एक बड़ा झटका दिया, जहां पार्टी न केवल एक भी सीट हासिल करने में विफल रही, बल्कि 2% से भी कम वोट शेयर हासिल कर पाई।

बुरी तरह हारे किसान आंदोलन के बड़े चहरे गुरनाम सिंह चढ़ूनी

चंडीगढ़। तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले चेहरों में से एक, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को मंगलवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही करारा झटका लगा। संयुक्त संघर्ष पार्टी के नेता, चढ़ूनी ने पिहोवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। लेकिन, वह केवल 1,170 वोट ही जुटा सके और उनकी जमानत जब्त हो गई। यहां मुकाबला कांग्रेस के मनदीप चट्ठा ने जीता, जिन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा के जय भगवान शर्मा के खिलाफ कुल 64,548 वोट हासिल किए। हालाँकि, चढ़ूनी के लिए, यह न केवल एक कष्टदायी हार थी, बल्कि कम से कम आलंकारिक रूप से चेहरे की क्षति भी थी। उन्होंने संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले लड़ाई लड़ी, जिसकी उन्होंने स्थापना की थी, लेकिन उनकी वोट संख्या उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत साबित हुई।

कांग्रेस पर फिर बरसे पीएम मोदी, हिंदूओं को बांटने का लगाया आरोप, बोले-

कांग्रेस को न विकास से मतलब, न विरासत से

नईदिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज महाराष्ट्र को 10 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम, शिरडी एयरपोर्ट के लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, आज इंफ्रास्ट्रक्टर से जुड़े इन दो अहम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी हुआ है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से, इतने बड़े स्केल पर अलग-अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ।

मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है, तब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। करोड़ों मराठी मानुष का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने जगह-जगह इसकी खुशी मनाई। आज महाराष्ट्र के गांव-गांव से मुझे खुशी के संदेश भी भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने संदेशों में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये काम मैंने नहीं, आप सबके आशीर्वाद ने किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगलवार को ही हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है कि देश का मिजाज क्या है। दो बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था। लेकिन कांग्रेस की सारी साज़िशें ध्वस्त हो गई। इन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की। लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोटबैंक को बांटना चाहती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के मन में भय का माहौल पैदा कर रही है। कांग्रेस लोगों का डर पालती है। कांग्रेस अपने वोट बैंक की खातिर देश का सांप्रदायिकरण कर रही है। मोदी ने कहा कि आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया। लेकिन किसानों को पता है कि उन्हें फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की। लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें-बेटियां अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं।

मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार-बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर-जिम्मेदार दल है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए-नए नरैटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फार्मूला लाती रहती है। कांग्रेस का फार्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोटबैंक में कन्वर्ट करो और वोटबैंक को मजबूत करों। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की नीति है, हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बंटेगा, उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है, ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेंकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं, वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है।

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय की परंपरा का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया, किसी देश में तभी विश्वास करती है, जब वहां का युवा आत्मविश्वास से भरा होता है। आज युवा भारत का आत्मविश्वास, भारत के भविष्य की नई कहानी है। दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत को मानव संसाधन के बड़े केंद्र के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को न विकास से मतलब था, न विरासत से मतलब था। हमारी सरकार में विकास भी है, विरासत भी है। हम अपने समृद्ध अतीत से प्रेरणा लेकर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।

राहुल ने हरियाणा के परिणाम को अप्रत्याशित बताया

नईदिल्ली। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के हालिया विधानसभा चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा, जम्मू-कश्मीर के लोगों का दिल से धन्यवाद। वहाँ की जीत संविधान की जीत है, यह लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। यह राहुल गांधी का पहला बयान था जिसमें उन्होंने चुनाव परिणामों का जिक्र किया और उन्होंने हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया।

राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव परिणामों का गहराई से विश्लेषण करने की बात कही और बताया कि पार्टी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों को चुनाव आयोग के समक्ष उठाएगी। उन्होंने हरियाणा के लोगों का आभार व्यक्त किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की, जिन्हें उन्होंने बब्बर शेर की उपमा दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 48 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस केवल 37 सीटों पर सिमट गई। यह बीजेपी की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी है, जो कि पार्टी की चुनावी रणनीति की सफलता को दर्शाता है।

चुनाव परिणामों के बाद, कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। पवन खेड़ा ने कहा, यह तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी नतीजों को स्वीकार नहीं कर सकती और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मतगणना के दौरान कई गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पार्टी के कई नेता चुनाव आयोग के पास जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, हम एक या दो दिन में चुनाव आयोग के पास जाएंगे। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें जीतना चाहिए था, लेकिन वहाँ हम हार गए हैं। यह नतीजे जनता की भावनाओं के खिलाफ हैं।

जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस ने स्पष्ट जनादेश मिलने की बात की है और राहुल गांधी ने इसे सकारात्मक रूप में लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जनता ने एक स्पष्ट संदेश दिया है और अब कांग्रेस राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जो विकास और स्थिरता को सुनिश्चित करेगा। इस तरह, चुनाव नतीजों ने हरियाणा में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, जहां कांग्रेस अपनी जीत के लिए जम्मू-कश्मीर की ओर देख रही है। बीजेपी की जीत ने एक बार फिर से पार्टी की चुनावी ताकत को प्रमाणित किया है, जबकि कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक ढांचे और रणनीतियों पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी का यह बयान और कांग्रेस के अन्य नेताओं के आरोप यह संकेत देते हैं कि वे चुनाव परिणामों को लेकर गंभीर हैं और आगे की रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं।

हरियाणा छोड़िए कांग्रेस को उत्तरप्रदेश में बड़ा झटका!

लखनऊ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहा है। उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना रुख आक्रमक रखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रेशर पॉलिटिक्स ने उसे झटका देना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बिना किसी गठबंधन के अंतिम मुहर लगे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी। समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ से तेज प्रताप यादव, फूलपुर से नसीम सोलंकी, मिल्कीपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, कटेहरी से अजित प्रसाद, मझवां से शोभावती वर्मा और बिंद से डॉ. ज्योति को मैदान में उतारा है। इससे पहले अखिलेश की तरफ से करहल सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। इससे कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है जो पहले से ही सीट शेयरिंग को लेकर आगे बढ़ रही थी।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बदले हुए समीकरणों के तहत समाजवादी पार्टी कांग्रेस को केवल एक सीट देने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने सपा से मांग की थी कि वो उसे वो सीटें जे जिन पर बीजेनी ने जीत हासिल की थी। हालांकि कांग्रेस की ये मांग न मान कर सपा और अखिलेश ने सहयोगी दल को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। सपा सिर्फ़ ग़ाज़ियाबाद शहर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट कांग्रेस को गठबंधन में देना चाहती है। यूपी में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में फूलपुर, मझवां, मीरापुर, खैर, सीसामऊ, करहल, कुंदरकी, मिल्कीपुर, कटेहरी व गाजियाबाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से नौ सीटें लोकसभा चुनाव के बाद रिक्त हुई हैं, जबकि कानपुर के सीसामऊ की सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद रिक्त हुई है।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान

नईदिल्ली। बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड टीम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत दौरे पर आएगी। इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम की घोषणा हो गई है। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम को श्रीलंका दौरे पर 2-0 का क्लीन स्वीप झेलना पड़ा। इसके बाद भी स्क्वॉड में बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, इस दौरान कप्तान जरूर बदला गया है। टॉम लैथम को टिम साउदी की जगह कप्तान नियुक्त किया गया है।

बता दें कि, न्यूजीलैंड की टी में मार्क चैपमैन को चोटिल केन विलियमसन के कवर के तौर पर चुना गया है। विलियमसन के पहले टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस है। इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल केवल पहला टेस्ट खेलेंगे। वह पिता बनने वाले हैं और स्वदेश लौट जाएंगे। उनकी जगह दूसरे और तीसरे टेस्ट में ईश सोढ़ी स्क्वॉड में जुड़ेंगे।

न्यूजीलैंड टेस्ट स्क्वॉड

टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (केवल पहला टेस्ट), मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, विल ओ%रुरके, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिशेल सेंटरन, बेन सियर्स, ईश सोढ़ी (केवल दूसरा और तीसरा टी20), टिम साउदी, केन विलियमसन, विल यंग।

भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज

16-20 अक्टूबर 2024- बेंगलुरु में सुबह 9.30 बजे पहला टेस्ट मैच

24-28 अक्टूबर 2024- पुणे में सुबह 9.30 बजे दूसरा टेस्ट मैच

1-5 नवंबर 2024- वानखेड़े में सुबह 9.30 बजे तीसरा टेस्ट मैच

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 168 अंक लुढ़का निफ्टी 25,000 के नीचे

नईदिल्ली। लगातार छह दिन की गिरावट के बाद कल जहां शेयर बाजार में रौनक लौटी थी, मगर वह आज फिर फीकी पड़ गई। बीआरआई एमपीसी के फैसले के बाद 9 अक्टूबर को बीएसई, एनएसई के बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। आज हैवी वेटेज वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक के शेयर 1% से ज्यादा गिर गए, जिसकी वजह से सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त बनाने में कामयाब नहीं हो सके। आज बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 0.21% या 167.71 अंक लुढ़ककर 81,467.10 के लेवल पर बंद हुआ। जबकि, एनएसई का बेंचमार्क निफ्टी 50 31.20 अंक या 0.12% गिरकर 24,981.95 के लेवल पर क्लोज हुआ। पिछले दिनों शेयर बाजार में गिरावट की वजह ईरान-इजराइल तनाव, कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी और विदेशी निवेशकों का चीनी बाजार की ओर रुख मानी जा रही थी।

आरबीआई ने रीपो रेट को रखा स्थिर

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार दसवीं बार नीतिगत दर रीपो को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने अपेक्षाकृत आक्रामक रुख को बदलकर 'तटस्थ' कर दिया। रुख में बदलाव का मतलब है कि आरबीआई मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि पर नजर रखते हुए जरूरत के हिसाब नीतिगत दर को बढ़ा या घटा सकता है। यह एक संकेत है कि मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक में नीतिगत दर में कटौती को लेकर संभवत- कदम उठाया जा सकता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सोमवार को शुरू हुई पहली बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, ''एमपीसी ने नीतिगत दर को यथावत रखने का निर्णय किया है।

आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ 7.2 फीसदी पर रखा बरकरार

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उपभोक्ता मांग तथा निवेश बेहतर रहने की संभावना के बीच चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के अनुमान को 7.2 प्रतिशत पर कायम रखा है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने दूसरी तिमाही के अपने वृद्धि दर के अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रही। पहले इसके 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही के अपने वृद्धि दर के अनुमान को क्रमश: 7.3 और 7.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया है।

एनबीएफसी को आरबीआई गवर्नर दास ने चेताया

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने बुधवार को उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी जो तेजी से आगे बढ़ने के लिए 'अस्थिर' तरीके अपना रही हैं। आरबीआई गवर्नर दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कड़े शब्दों में ऐसी एनबीएफसी से ईमानदार, निष्पक्ष रहने और टिकाऊ व्यवहार का पालन करने को कहा। दास ने कहा, '' यह महत्वपूर्ण है कि एमएफआई (सूक्ष्म वित्त संस्थान) और एचएफसी (आवास वित्त कंपनियां) सहित एनबीएफसी स्थायी व्यावसायिक लक्ष्यों का पालन करें।''अनुपालन सर्वप्रथम'' संस्कृति अपनाएं, एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा अपनाएं, निष्पक्ष व्यवहार संहिता का कड़ाई से पालन करें और ग्राहकों की शिकायतों पर ईमानदारी से गौर करें।''

स्वर्ण ऋण के प्रति बढ़ता भारतीयों का रुझान

प्रह्लाद सबनानी

किसी भी देश के आर्थिक विकास को गति देने हेतु पूंजी की आवश्यकता रहती है। तेज आर्थिक विकास के चलते यदि किसी देश में वित्तीय बचत की दर कम हो तो उसकी पूर्ति ऋण में बढ़ोत्तरी से की जा सकती है। भारत में ऋण- सकल घरेलू अनुपात अन्य विकसित एवं कुछ विकासशील देशों की तुलना में अभी बहुत कम है। परंतु, हाल ही के समय में भारत का सामान्य नागरिक ऋण के महत्व को समझने लगा है एवं भौतिक संपति के निर्माण में अपनी बचत के साथ साथ ऋण का भी अधिक उपयोग करने लगा है। कुछ बैंक सामान्यजन को ऋण प्रदान करने हेतु प्रतिभूति की मांग करते है। भारत में सामान्यजन के पास स्वर्ण के रूप प्रतिभूति उपलब्ध रहती है अत: स्वर्ण ऋण बहुत अधिक चलन में आ रहा है। विशेष रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा ऋण की प्रतिभूति के विरुद्ध स्वर्ण ऋण आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में तेजी से बढ़ रहे स्वर्ण ऋण के कारणों एवं कारकों का वर्णन इस लेख में किया गया है।

भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही में विभिन्न गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा 39,687 करोड़ रुपए के स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए गए थे, स्वीकृत की जाने वाली यह राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में बढ़कर 62,835 करोड़ रुपए हो गई एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में और आगे बढ़कर 79,218 करोड़ रुपए हो गई। गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में स्वर्ण ऋण के मामले में 26 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर हासिल की है जबकि अन्य प्रकार के ऋणों में इसी अवधि के दौरान औसत वृद्धि दर 12 प्रतिशत की रही है।

भारतीय नागरिक स्वर्ण ऋण के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो रहे हैं। आज भारत के विभिन्न गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों एवं विभिन्न बैंकों द्वारा भारी मात्रा में स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं। अगस्त 2024 माह में बैंकों एवं गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनियों ने मिलकर 41 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करते हुए 1.4 लाख करोड़ रुपए के स्वर्ण ऋण स्वीकृत किए हैं। आज गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कुल ऋण में स्वर्ण ऋण का प्रतिशत में हिस्सा सबसे अधिक है, दूसरे स्थान पर स्कूटर एवं चार पहिया वाहनों के लिए प्रदान किए गए ऋणों का ऋण हैं, इसके बाद तीसरे स्थान पर व्यक्तिगत ऋण 14 प्रतिशत के भाग के साथ है एवं इसके बाद जाकर गृह ऋण का नम्बर आता है जो कुल ऋण का 10 प्रतिशत भाग है। बैकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्वर्ण ऋण पर पूंजी पर्याप्तता सम्बंधी शिथिल नियमों का पालन करना होता है। अन्य प्रकार के ऋणों की तुलना में स्वर्ण ऋण पर जोखिम का भार (रिस्क वेट) तुलनात्मक रूप से कम रहता है। इससे बैंक एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां भी स्वर्ण ऋण प्रदान करने की ओर आकर्षित होते हैं।

यहां स्वाभाविक रूप से प्रशन्न उभरता है कि पिछले लगभग 3 वर्षों के दौरान भारत के नागरिकों में स्वर्ण ऋण के प्रति इतना रुझान क्यों बढ़ा है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण के भंडार बढ़कर 822 मेट्रिक टन से भी अधिक हो गए हैं परंतु विश्व स्वर्ण काउन्सिल के एक अनुमान के अनुसार, भारतीय नागरिकों के पास स्वर्ण के भंडार बढ़कर 25000 टन से भी अधिक के हो गए हैं, जिनकी बाजार कीमत वर्ष 2020 में 109 लाख करोड़ रुपए की थी।

भारत में नागरिकों के पास स्वर्ण भंडार विश्व के कुल स्वर्ण भंडार का 11 प्रतिशत है। भारत में प्रतिवर्ष 750 से 800 टन स्वर्ण का आयात होता है और पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में 17,500 टन स्वर्ण का आयात हुआ है और मार्च 2019 से मार्च 2024 के दौरान भारत में स्वर्ण भंडार 40 प्रतिशत से बढ़ गए हैं। दरअसल, भारत में दीपावली (धन तेरस) के शुभ अवसर पर स्वर्ण की खरीद को शुभ माना जाता है एवं मध्यमवर्गीय परिवार भी धन तेरस के दिन स्वर्ण की खरीद प्रति वर्ष करते हैं। इससे भारत के करोड़ों परिवारों के पास स्वर्ण का स्टॉक उपलब्ध रहता है।

भाजपा सदस्यता अभियान : छग में 36 लाख का आंकड़ा पार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा सदस्यता अभियान में 36 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 36 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। भाजपा के सदस्यता अभियान को प्रदेशभर में जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और जो लोग ऑनलाइन सदस्य नहीं बन पा रहे हैं, उनकी मांग को देखते हुए प्रदेश में अब फार्म भरकर ऑफलाइन सदस्य बनाने का अभियान भी युद्धस्तर पर चल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश की जनता-जनार्दन में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने का उत्साह देखकर यह असंदिग्ध है कि आने वाले कुछ ही दिनों में प्रदेश में भाजपा के 50 लाख से अधिक सदस्य बना लिए जाएंगे।

भाजपा सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा ने विशेष अभियान भी चलाकर सदस्यता के लक्ष्य की प्राप्ति में बड़ी छलांग लगाई है, जिनमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव व विजय शर्मा समेत प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, सांसद-विधायक, पदाधिकारी व कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुँचकर सदस्यता के लक्ष्य को पार करने में लगातार जुटे हुए हैं। सदस्यता अभियान को और तेज गति देने के लिए 6 और 7 अक्टूबर को एक बार पुनः विशेष सदस्यता अभियान चलाया गया जिसमें प्रदेश में 4 लाख सदस्य बनाए गए। अब तक ऑनलाइन सदस्य बनाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में अब ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है। प्रदेश में अब तक भाजपा के 36 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। इधर सदस्यता को गति प्रदान करने प्रदेश के सभी पाँच संभागों से भारतीय जनता युवा मोर्चा की 20 रथयात्राएँ प्रारंभ हो चुकी हैं। पार्टी के सभी मोर्चा-प्रकोष्ठों को भी अभियान की सफलता के लिए लक्ष्य सौंपकर जिम्मेदारी दी गई है। सिंहदेव ने कहा कि नमो एप, वेब साइट की लिंक, रेफरल लिंक और मिस्ड कॉल के जरिए सदस्या अभियान को गति देने के बाद पार्टी कार्यकर्ता पूरे समर्पण के साथ जिन क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है या जिन लोगों को ऑनलाइन सदस्य नहीं बनाया जा सक रहा हो, वहाँ घर-घर सम्पर्क करके फार्म भरकर ऑफलाइन सदस्यता के अभियान में जुट गए हैं। सिंहदेव ने 36 दिनों में छत्तीसगढ़ में 36 लाख सदस्य बनाने के लिए सभी पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का आभार मानते हुए बधाई दी और विश्वास जताया कि अगले कुछ ही दिनों में पार्टी प्रदेश में सदस्य संख्या के 50 लाख के आँकड़े को पार करेगी।

सिंहदेव ने कहा कि इसी के साथ पार्टी के सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान भी शुरू होने जा रहा है। प्रत्येक मंडल में 200 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। प्रदेशभर में चलने वाले सक्रिय सदस्यता अभियान के लिए भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव को सक्रिय सदस्यता अभियान का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर सतत समीक्षा का क्रम भी प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में चल रहा है। अभी हाल ही भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल व प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की उपस्थिति में हुई बैठक में जिला अध्यक्ष एवं जिला सदस्यता प्रभारी और महामंत्रियों से जिलेवार चर्चा करके सदस्यता के लिए लक्ष्य तय किया गया।

छत्तीसगढ़ में चार नवीन जिला सहकारी बैंक के गठन की प्रक्रिया प्रारंम्भ

सहकारिता मंत्री कश्यप ने की विभागीय समीक्षा

सहकारिता मंत्री 'सहकार से समृद्धि' एक दिवसीय कार्यशाला में हुए शामिल

राज्य के 8.36 लाख से अधिक किसानों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन, जलसंसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप आज सिविल लाईन रायपुर स्थित न्यू-सर्किट हाउस, मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में 'सहकार से समृद्धि' विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में केंद्र सरकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'सहकार से समृद्धि' विषय पर की गई पहल के अंतर्गत राज्य में किए जा रहे विभिन्न कार्यों के विषयों पर आयोजित की गई। गौरतलब है कि सहकारी बैंक द्वारा 8 लाख 36 हजार 597 किसानों को रूपे किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने 5 किसानों को प्रतिकात्मक रूप से रूपे किसान क्रेडिट कार्ड और श्रीमती नीलम चौहान को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

विभागीय समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी 6 माह में 2000 पैक्स, मछुआ समिति, लघुवनोपज समिति तथा दुग्ध समितियों का गठन किया जाना है। इसके लिए मल्टी फंक्शनल सोसाइटियों के मॉडल बायलॉज तथा समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए। अधिकारियों ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आरआईडीएफ के तहत 200 मीट्रिक टन क्षमता के 725 पैक्स गोदामों में से 587 गोदाम निर्माण पूर्ण हो चुका है। शेष गोदामों का निर्माण नवंबर माह तक पूर्ण करा लिया जाएगा, इससे छत्तीसगढ़ में 1.45 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। सहकारिता मंत्री ने मछुआ सहकारी समितियों की नीतियों में सुधार के लिए निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ के मछुवारों को मछली विक्रय का लाभ सीधे मिल सके एवं उनका हित सुरक्षित रहे। छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के अधीन 42 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अक्टूबर माह के अंत तक खोलने के निर्देश दिए, जिससे लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाई मिल सकेगी। बैठक में अम्बिकापुर तथा जगदलपुर के सभी पैक्स में माइक्रो एटीएम को एक्टिव रखने कहा गया। जिससे आगामी धान खरीदी में किसानों को राशि आहरण में सुविधा हो। डेयरी समितियों तथा मछुआ समितियों को माइक्रो एटीएम दिया जाए।

सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि पैक्स कंप्यूटराईजेशन मॉड्यूल किसानों के लिए उपयोगी होना चाहिए। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, कोंडागांव, सरगुजा, सारगढ़ तथा बलौदाबाजार जिले के पैक्स कंप्यूटराईजेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने कहा गया। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के मापदंडों का अनुपालन करते हुए छत्तीसगढ़ में चार नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के गठन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। महासमुंद तथा गरियाबन्द को मिलाकर नवीन बैंक, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा तथा शक्ति को मिलाकर एक नवीन बैंक, कांकेर तथा नारायणपुर को मिलाकर नवीन सहकारी बैंक एवं रायगढ़, जशपुर व सारंगढ़ मिलाकर नवीन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खोली जाएगी।

सचिव सहकारिता डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2058 पैक्स में 1738 कॉमन सर्विस सेंटर एक्टिवेट किया गया है। इन कॉमन सर्विस सेंटरों से सहकारी समितियों के 16 लाख ऋणी सदस्यों को जोड़ा जाएगा। डेयरी तथा मछुआ समितियों का खाता को-आपरेटिव्ह बैंकों में खोला जाए। बैठक में भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता की स्थिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति की सदस्यता, राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति की सदस्यता तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत एलपीजी वितरण पैक्स की गहन समीक्षा की गई।

बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा

रायपुर। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी एवं राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पदेन अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति श्रीमती शम्मी आबिदी की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुई। सचिव महिला एवं बाल विकास द्वारा बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर एवं विभिन्न विभागों के साथ समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती तुलिका प्रजापति एवं अन्य सहयोगी विभागों गृह विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण, रेलवे एवं एनआईसी आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों में समयबद्ध कार्यवाही हेतु रणनीति, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान एवं मिशन वात्सल्य के तहत की गई गतिविधियों व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में मुख्य सचिव द्वारा भी विधि विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा गृह विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली गई थी। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य बाल संरक्षण समिति की बैठक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम-2020 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथासंशोधित अधिनियम-2021 तथा नियम 2016 यथासंशोधित नियम-2022 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

पीडब्ल्यूडी विभाग में 102 सब इंजीनियरों की होगी भर्ती

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेजी से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए हैं। इसके परिपालन में रिक्त पदों पर भर्ती की त्वरित रूप से स्वीकृति दी जा रही है। मुख्यमंत्री की विशेष पहल से अबतक शासकीय सेवा के 6 हजार से अधिक पदों में नियुक्तियों की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इसी कड़ी में अब सीएम साय के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियरों के 102 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है। इसमें 86 सिविल और 16 विद्युत-यांत्रिकी के उप अभियंता के पद शामिल हैं। इससे पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 128 अभियंताओं के पद निकाले गए थे।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में अवसर लगातार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में लगातार पहल की जा रही है। अब तक 8 से अधिक विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ हो गई है।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। निर्माण एजेंसियों में तेजी से चल रही भर्ती प्रक्रिया से प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रही अधोसंरचना परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

पूर्व विधायक की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन और विधानसभा सचिव को जारी किया नोटिस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक मिश्रीलाल खत्री की पत्नी पुष्पा देवी खत्री द्वारा दायर याचिका पर राज्य शासन और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. पुष्पा देवी ने अपने पति की पेंशन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन और पेंशन नियम 2006 के नियम 3 घ की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. याचिका में बताया गया कि कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कोई भी नियम मूल अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर सकती. बता दें कि पुष्पा देवी खत्री अपने अधिवक्ता के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. याचिका के मुताबिक उनके पति मिश्रीलाल खत्री संजारी बलोद जो, कि वर्तमान में विलोपित के पूर्व विधायक थे. उनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1979 तक था. उनका 1996 में निधन हो गया. पूर्व विधायक के निधन के बाद नियमानुसार राज्य शासन ने पेंशन बंद कर दी. याचिका के अनुसार दिवंगत पूर्व विधायक की पत्नी ने कुटुंब पेंशन के लिए राज्य शासन व सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा के समक्ष आवेदन पेश किया था. इसे खारिज कर दिया. सचिव ने लिखा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन तथा पेंशन नियम 2006 के नियम 3 घ के अनुसार कुटुंब पेंशन केवल उन प्रकरणों में प्रदान की जा सकेगी जिसमें पूर्व विधानसभा सदस्य की मृत्यु 2005 के बाद हुई हो. वर्तमान प्रकरण में पूर्व विधायक मिस्त्री लाल खत्री की मृत्यु 1996 में हो चुकी है, लिहाजा पेंशन नहीं दी जाएगी.

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

सरकार डीएड शिक्षकों के संबंध में तुरंत निर्णय लें

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में अराजक स्थिति निर्मित हो गई है। सरकार में बैठे लोग माननीय न्यायालय के आदेश को लागू नहीं कर रहे हैं न ही युवाओं की आवाज को सुन रहे हैं। न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए डीएड के अभ्यर्थी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गृह मंत्री के आवास पर प्रदर्शन कर रहे हैं कभी भीख मांग कर तो कभी सिर मुड़वा कर आदेश को लागू करने की मांग कर रहे हैं। आज तो अजब स्थिति हो गई जब डीएड के अभ्यर्थियों को माननीय न्यायालय के फैसला को लागू कराने के लिए जल सत्याग्रह करना पड़ा है। आखिर सरकार में बैठे लोग चाहते क्या हैं? प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार तत्काल 35000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करें। बीएड और डीएड वालों के बीच के विवाद को खत्म करें। न्यायालय के फैसला को लागू करें। लेकिन सरकार न न्यायालय का सम्मान कर रही है न युवाओं को रोजगार देना चाहती है। सरकार में बैठे लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश के नौनिहालों को अच्छी शिक्षा मिले स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो बच्चे शिक्षित हो और देश प्रदेश के भविष्य बने।

साय सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण जनता पर कर्ज बढ़ा

रायपुर। साय सरकार की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि साय सरकार ने रिजर्व बैंक को एक बार फिर 1000 करोड़ के प्रतिभूति को बेचने का प्रस्ताव दिया है। साय सरकार ने 10 माह में कर्ज लेने का नया रिकार्ड बनाया है। एक वित्तीय वर्ष मे छत्तीसगढ़ ने कर्ज लेने का नया रिकार्ड बनाया है। राज्य ने एक वित्तीय वर्ष मे 32000 करोड़ का कर्ज लिया है। कांग्रेस के सरकार ने 5 साल में 50 हजार करोड़ का कर्ज लिया था। साय सरकार को एक साल भी नहीं हुआ 32000 करोड़ का कर्ज ले लिया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के बाद भी सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है। साय सरकार ने रिजर्व बैंक से 10 माह में हर महीने औसतन 3200 करोड़ कर्ज लिया है। सरकार चलाने वालों को 10 माह में ही पसीना निकल गया। तथा सरकार का आर्थिक प्रबंधन गड़बड़ा गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में जनता के खाते में सीधे 2 लाख करोड़ डाला था। वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता, गोबर खरीदी, गोठान संचालन, युवा मितान क्लब सभी कुछ बंद कर दिया उसके बाद सरकार कर्ज पर कर्ज लिये जा रही है।

सांसद बृजमोहन ने किया दशहरा उत्सव स्थल का भूमि पूजन

रायपुर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को दुधाधारीमठ, रावणभाठा में सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति द्वारा आयोजित भूमि पूजन के कार्यक्रम में भाग लिया। आगामी विजयादशमी महोत्सव की तैयारियों को दुरुस्त करने हेतु चर्चा की। सांसद अग्रवाल ने दशहरा उत्सव में आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित रखने एवं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम, सीएसईबी, पीडब्ल्यूडी और पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली और दशहरा उत्सव से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से यातायात व्यवस्था दुरस्त करने के लिए आने वाले वाहनों के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था करने को कहा साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों से दशहरा उत्सव के दौरान अबाधित बिजली आपूर्ति के लिए अतिरिक्त जेनरेटर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पीडब्ल्यूडी अधिकारी को सही से बैरिकेटिंग करने के लिए कहा जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। बृजमोहन अग्रवाल ने दशहरा मैदान में 40 लाख की लागत से निर्माणाधीन टेनिस कोर्ट का निरीक्षण भी किया और निगम के जोन 6 कमिश्नर रमेश जायसवाल को वहां अतिरिक्त सुविधा बढ़ाने और वॉलीबॉल कोर्ट निर्माण करने के भी निर्देश दिए।

तक्षशिला लाइब्रेरी में युवाओं की सुविधा के लिए मौजूद है कैंटीन

रायपुर। रायपुर के तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन एवं लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आने वाले युवाओं को चाय-कॉफी, नाश्ता और भोजन के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। संस्कृति स्वसहायता समूह द्वारा यहां संचालित कैंटीन में सभी कुछ मौजूद है। मंगलवार को तक्षशिला लाइब्रेरी की व्यवस्था देखने आए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी युवाओं से चर्चा करते यहां के फरा-चटनी, सैंडविच और कुल्हड़ में चाय का स्वाद लिया। उन्होंने इनके स्वाद की तारीफ भी की। उप मुख्यमंत्री साव ने तक्षशिला लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं के साथ ही यहां स्वसहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन के इंतजाम का भी जायजा लिया। उन्होंने समूह की महिलाओं से चर्चा कर यहां बनाए जाने वाले व्यंजनों, उनकी बिक्री और आमदनी की जानकारी ली। रायपुर नगर निगम द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत समूह को यहां कैंटीन के संचालन के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है। इससे जहां स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, वहीं लाइब्रेरी में पढ़ने आने वाले युवाओं को कम दरों पर चाय-कॉफी, नाश्ता और भोजन सुलभ हो रहा है। उप मुख्यमंत्री साव को संस्कृति स्वसहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती रोशनी सोनी ने बताया कि अप्रैल-2024 से समूह द्वारा तक्षशिला लाइब्रेरी में कैंटीन का संचालन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने नवरात्रि में गरबा की तर्ज पर करवा रहे सुवा नृत्य

रायपुर। राजधानी के डी.डी. नगर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में माता जस तिहार का आयोजन किया जा रहा है. माता की आराधना करने मांदर की धुन में जस गीत गाया जाता है. प्रतिदिन शाम 8 बजे से 11 बजे तक सुवा नृत्य, करमा नृत्य, पंथी नृत्य, राउत नाचा, बस्तरिहा नृत्य, सरगुजीहा नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजधानी के महिला, पुरुष, बच्चे बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. छत्तीसगढ़ी लुगरा में सजी महिलाएं पूतरी, ऐंठी, सुता आदि छत्तीसगढ़ी सवांगा पहनकर सुवा करती हैं. पुरुष भी परिवारजनों के साथ शामिल होकर नृत्य कर रहे हैं. लंदन निवासी भूपेंद्र कौशिक अपने स्वर्गीय पिता नारायण प्रसाद कौशिक की स्मृति में माता जस तिहार का आयोजन सांस्कृतिक परिपालन समिति के साथ मिलकर कर रहे हैं. राजधानी में इस प्रकार के अनूठे आयोजन का विचार कैसे आया, पूछने पर समाज सेविका ऋचा वर्मा ने बताया कि युवा पीढ़ी गरबा करना तो जानती है, लेकिन छत्तीसगढ़ी संस्कृति से दूर होती जा रही है. अपनी जन्मभूमि का मान बढ़ाने और सांस्कृतिक पहचान को दूर-दूर तक फैलाने के उद्देश्य से इस आयोजन का विचार आया. भूपेंद्र कौशिक ने बताया कि लंदन में छत्तीसगढ़ के बारे में पूछने पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता.

35th वेस्ट ज़ोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप

नागपुर में छत्तीसगढ़ के एथलीटों ने जीता 34 पदक

रायपुर। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 35th वेस्ट ज़ोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 दिनांक 04 से 06 अक्टूबर 2024 तक नागपुर (महाराष्ट्र) मे आयोजित किया गया । इस प्रतियोगिता मे गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ आदि 6 राज्य के खिलाड़ी भाग ले रहे है । इस प्रतियोगिता मे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करे 34 पदक प्राप्त किया एवं प्रतियोगिता मे चौथे नंबर पर रहा।

गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों मे- कु. मानस्वी भगत (-18 गर्ल्स) लॉन्ग जंप, कु. चाँद भारद्वाज (-18 गर्ल्स) 100 मीटर रेस, सिया सिंह (-20 गर्ल्स) 400 मीटर दौड़, कु? सांधनी साहू (-18 गर्ल्स) शॉटपुट, अमित कुमार चावडा (-20 बॉयस) 100 मीटर रेस, मोहित सिंह (-16 बॉयस) जैवलिन थ्रो, राजेश इस्ताम (-14 बॉयस) किड्स जैवलिन थ्रो

सिल्वर मेडल प्राप्त करने वालों मे- कुमारी तानिया केवट (-18 गर्ल्स) 400 मी रेस, कुमारी दामिनी (-20 गर्ल्स) लॉन्ग जंप, आशुतोष तिवारी (अंडर 20 बॉयज) 1500 मी रेस, नमेश कुमार चंदेल (अंडर 20 बॉयज) 400 मी रेस, टी. होमेश्वर राव (अंडर 18 बॉयज) 100 मी रेस, कु. जानवी निषाद (-20 गर्ल्स) जैवलिन थ्रो, कु. सुशीला (अंडर 14 गर्ल्स) 600 मी रेस, अमित कुमार चावडा अंदर (अंडर 20 बॉयज) 200 मी रेस, कु? नंदिनी साहू (अंडर 18 गर्ल्स) 200 मी रेस, यश कुमार (अंडर 18 बॉयज) 5000 मी. रेस वॉक, कु. देविका यादव (अंडर 18 गर्ल्स) 3000 मीटर रेस वॉक, भूपेश मांडवी अंडर (अंडर 20 बॉयज) 800 मी. रेस, कु. सपना मेश्राम (-20 गर्ल्स) 400 मी हर्डल्स।

ब्रांज़ मेडल प्राप्त करने वालों मे0 कु? नीता सलामे (-20 गर्ल्स) 5000 मी? रेस, कु? चंद्रमा नेताम (-20 गर्ल्स) 100 मी हर्डल्स, कु. दार्शनिक (-18 गर्ल्स) 100 मी हर्डल्स, कु. अश्विन (-16 गर्ल्स) पेंटाथलन, कु. इशा रानी (-18 गर्ल्स) 1000 मी. रेस, कु. रेणुका (-20 गर्ल्स) डिस्कस थ्रो, तेजस गोड (-16 बॉयज) लॉन्ग जंप, राहुल (अंडर 20 बॉयज) 400 मी. रेस, शुभम कुमार साहू (अंडर 20 बॉयज) 10000 मी. रेस, राम चरण (अंडर 18 बॉयज) डिस्कस थ्रो, हर्ष निषाद (अंडर 18 बॉयज) 1000 मी. रेस, रेमंन साहू (अंडर 20 बॉयज) 3000 मी? स्टेपलचेज, अनंतराम (अंडर 18 बॉयज) लॉन्ग जंप। इस प्रतियोगिता मे सबसे ज्यादा पदक बिलासपुर जिला से 9, बालोद से 6, दंतेवाड़ा से 3, दुर्ग से 3, रायपुर से 2, जयपुर से 2, महासमुंद से 2, सूरजपुर से 1, धमतरी से 1, राजनांदगांव से 1, बलौदा बाजार से 1 एवं सरगुजा से 1 इस प्रकार कुल 34 मे 07 गोल्ड, 14 सिल्वर एवं 13 ब्रांज़ मेडल छत्तीसगढ़ के एथलीटों के नाम रहा। उपरोक्त प्रतियोगिता मे प्रशिक्षक एवं प्रबंधक के रूप मे बिलासपुर एथलेटिक्स अकैडमी के द्रोणाचार्य अवार्डी कोच एस भाटिया, सुदर्शन कुमार सिंह, कामता प्रसाद यादव, सुनीति निषाद, दामिनी सिंह, संदीप कुमार, कु. आंचल भगत आदि के अतिरिक्त 12 अभिभावक भी उपस्थित हुए ।

केंद्र सरकार महंगाई को रोकने का कोई ठोस प्रयास नहीं कर रही: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को रोकने का कोई ठोस प्रयास नहीं कर रही। देश की जनता का महंगाई से बुरा हाल है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, महंगाई से देश के नागरिकों की कमर टूटती जा रही है।ॉ

मोदी राज में रोजमर्रा की जरूरतों के दाम बेतहाशा बढ़ गये है। 2014 में जो गैस का सिलेंडर 410 रु. का था, आज वह 1000 रु. के पार है। पेट्रोल के दाम 70 रु. प्रति लीटर से बढ़कर 100 रु. प्रति लीटर के पार हो गए हैं जबकि डीजल के दाम 55 रु. प्रति लीटर से बढ़कर 95 रु. प्रति लीटर के करीब पहुंच गए हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड आयल का दाम लगातार कम हो रहे है। 2014 की तुलना में वर्तमान में क्रूड आयल आधे रेट में मिल रहा है, लेकिन उसका लाभ आम जनता को नही मिल रहा है। खाने के तेल और दाल की कीमत 70 रु. और 60 रु. प्रति किलो थी, वह 200 रू. प्रति किलो को पार कर गई है।

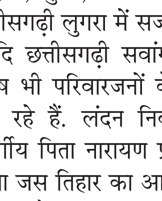

इतना ही नहीं, बीते दिनों जीएसटी की बर्बर मार से दही, पनीर, लस्सी, आटा, सूखा सोयाबीन, मटर व मुरमुरे भी बच नहीं सके, उन पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगा दिया गया। होटल के 1,000 रु. के कमरे पर 12 प्रतिशत जीएसटी, अस्पताल के आईसीयू बेड पर 5 प्रतिशत जीएसटी। जीने के लिए सभी आवश्यक चीजों पर जीएसटी लगाकर चैन नहीं मिला तो श्मशान घाट के निर्माण पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार घट रही है। मगर मोदी सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम नहीं कर रही है। बीते 10 सालों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कर लगाकर 29 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से निकाले गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने में असफल और नकारा साबित हुई है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.